कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

कार्तिक–मार्गशीर्ष 2075, नवंबर 2018

विराट, विलक्षण, बेबाक
दत्तोपंत ठेंगड़ी

VOICE OF SELF RELIANT INDIA

SWADESHI Patrika

स्वदेशी पत्रिका

वार्षिक सदस्यता **(Annual Subscription) :** **150/-**

आजीवन सदस्यता **(Life Membership) :** **1500/-**

For subscription please send payment by A/c payee Cheque/Demand Draft/Money Order in favour of 'Swadeshi Patrika' at New Delhi, or Deposit the subscription amount in

Bank of India, *A/c No.* **602510110002740,**
IFSC: BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

Kindly write your full name and address in capital letters.
If you do not receive any issue of Swadeshi Patrika, kindly e-mail us immediately or contact **Sh. Suraj Bhardwaj (9899225926)**

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–26, अंक–11
कार्तिक–मार्गशीर्ष 2075, नवंबर 2018

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-37

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–6

विराट, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी दत्तोपंत ठेंगड़ी

स्वदेशी संवाद

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 विशेष
संघ विचार के महान भाष्यकार श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी
.... डॉ. श्रीपति शास्त्री

10 आर्थिकी
नहीं है भारत में आर्थिक संकट
.... डॉ. अश्वनी महाजन

12 मीडिया
पत्रकारों के खिलाफ हिंसा में दंडमुक्ति के खात्मे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
.... अनिल तिवारी

16 पड़ताल आकलन
सूखा या बाढ़ नहीं, किसान की त्रासदी है माटी मोल कीमतें
.... देविन्दर शर्मा

18 आकलन
ट्रेड वार का सार्थक पहलू
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

20 समीक्षा
नोटबंदी – एक आर्थिक फैसला
.... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

22 अभियान
भारत का मिशन गगनयानः चांद पर जाने की तैयारी
.... निरंकार सिंह

25 मुद्दा
जनता से जुड़े मुद्दे उठाना कब शुरू करेंगे राजनीतिक दल?
.... शिवाजी सरकार

28 आजकल
गंगा–पुत्र स्वामी सानंद का आत्मोत्सर्ग
.... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

31 कृषि
जीएम फसलों द्वारा पारिस्थितिकी असंतुलनः वैज्ञानिक सत्य
.... डॉ. रेखा भट्ट

38 स्वदेशी गतिविधियां
स्वदेशी मेला – दिल्ली

पाठकनामा

भूख एक लाइलाज बीमारी

विचारणीय कोई खा–खां के मरता है, तो कोई भूखा रहकर। यह दंतकथा प्रचलित होने के साथ फलीभूत भी है। ये दोनों ही हालात में भूख को लाइलाज बीमारी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड रहे है। लिहाजा, भूख और कुपोषण एक सिक्के के दो पहलू हैं। बच्चों में कुपोषण के बहुत सारे लक्षण होते है, जिनमें से अधिकांश गरीबी, भूखमरी और कमजोर पोषण से संबंधित हैं। सामान्य रूप से भारत में बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति एक चिंता का विषय हैं। यूनेस्को की रिर्पोट में भारत में कुपोषण सब–सहारा अफ्रीका की तुलना में अधिक पाया था। विश्व के एक तिहाई कुपोषित बच्चे भारत में ही पाए गए। कुपोषण बच्चे के विकास तथा सीखने की क्षमता को अवरूद्ध कर देता हैं। इससे बच्चों की मृत्यु भी हो सकती हैं। अमुमन जिन बच्चों की बचपन में मृत्यु हो जाती है उनमें 50 फीसदी बच्चे कुपोषण के कारण मरते हैं। भारत में तीन वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों में से 46 प्रतिशत अपनी आयु की दृष्टि से बहुत छोटे लगते हैं। लगभग 47 प्रतिशत बच्चे कम भार के होते हैं और लगभग 16 प्रतिशत की मृत्यु हो जाती हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं।

दरअसल, हमारे देश में पोषण एक मात्र पेट भरने का तरीका है। चाहे वह किसी भी तरह से क्यों ना हो, भूख मिटनी चाहिए। उसके लिए कुछ भी खाना क्यों ना पडे। पोषक तत्वों की फ्रिक किसे हैं। भूख दुनिया की सबसे बडी लाइलाज बीमारी बनती जा रही हैं। इसी जद्दोजहद में भिक्षावृत्ति, वेष्यावृत्ति, बाल मजदूरी और चोरी करना आम बात हो गई हैं। सवाल यह उत्पन्न होता हैं कि आम इंसान दो वक्त की रोटी कहां से जुगाड़ करे। सरकारों, हुक्मरानों या भगवान भरोसे रहे, या खाली पेट रहकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। यह कोई समस्या का सर्वमान्य निदान नहीं हैं। समाधान मिलेगा कृषि और स्वरोजगार के संवहनीय आजीविका के साधनों में। जरूरत हैं तो खेती में सम्यक् आमूलचूल परिवर्तन तथा निचले स्तर तक रोजगार के संसाधन विकसित करने की। वह आएगा, जल, जंगल, जमीन व पशुधन के संरक्षण और संर्वधन से। अभिष्ट खेती और पंरपरागत व्यवसायों में कौशल विकास का अभिवर्द्धन ऐसा साधन हैं, जो सभी को भूख से बचा सकती हैं। तब कहीं जाकर भूख की लाइलाज बीमारी जडमूल से नष्ट होगी।

हेमेन्द्र क्षीरसागर, *ग्वालियर (मध्य प्रदेश)*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

नए भारत के निर्माण के लिए भ्रष्टाचार का समूल नाश करना पहली शर्त है। भ्रष्टाचार उस दीमक की तरह है जो आर्थिक तंत्र को तो खोखला करता ही है, वह सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर भी बुरा प्रभाव डालता है।

महामहिम रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति, भारत

दुनिया के महान सिद्धांतों को अपनाने के बाद भी, देश की प्रगति के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी दार्शनिक नींव के आधार पर अपने स्वयं के औद्योगिक विकास के विशिष्ट मॉडल तैयार करें।

डॉ. मोहन भागवत
सरसंघचालक, आर.एस.एस.

देश में 'आसान कार्य व्यापार' में भारत की छलांग से यह साबित हो गया है कि हम आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और इससे औद्योगिक विकास में तेजी के साथ-साथ निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

मुक्त व स्वतंत्र भारत-प्रशांत क्षेत्र के बड़े लक्ष्य के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना चाहता हूं।

शिंजो एबे
राष्ट्रपति, जापान

संपादकीय

विदेशी कंपनियों द्वारा रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क भुगतान पर लगे सीमा

लगातार रूपये के अवमूल्यन के मद्देनजर, स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क के नाम पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन पर सीमा लगाने हेतु गुहार लगाई है। पत्र में कहा गया है कि डॉलर के बदले रूपये में एक रूपये का अवमूल्यन, देश के तेल आयात बिल को 2 अरब डालर बढ़ा देता है, यह बात हाल ही में किए गये सांख्यिकी अनुमानों से सामने आई है। आज जब 2018 वर्ष के प्रारंभ से अभी तक जो रूपया डालर के मुकाबले 6 रूपये नीचे आ गया है, इसका मतलब यह है कि देश को 12 अरब डालर का नुकसान केवल तेल के आयात में ही हो जायेगा।

पत्र में प्रधानमंत्री जी से कहा गया है कि रूपये में लगातार होते भारी अवमूल्यन के पीछे विदेशी कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क के नाम पर विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन है। कहा तो यह जाता है कि पेटेंट, कॉपीराइट, लाईसेंस या फ्रेंचाईजिज़ के बदले ये शुल्क दिये जाते है। लेकिन सच्चाई यह है कि रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क के बहाने भारत सरीखे विकासशील देशों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर ले जाती हैं। 2017–18 में जबकि देश में कुल 61 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क के नाम पर 20.6 अरब डालर भारत से उड़न–छू हो गये। यानि विदेशी निवेश से होने वाले विदेशी मुद्रा के संभावित लाभ रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क के कारण नहीं हो पाये। गौरतलब है कि आगे चलकर जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त भी नहीं होगा तो भी रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क का भुगतान जारी रहेगा।

2009 से पहले रॉयल्टी के भुगतान सरकार द्वारा नियंत्रित थे और उनकी सीमा निर्यात के संदर्भ में 8 प्रतिशत और घरेलू बिक्री के संदर्भ में 5 प्रतिशत थी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी समझौतों में ट्रेडमार्क और ब्रांड के नाम के उपयोग हेतु यह सीमा निर्यातों और घरेलू बिक्री के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत थी। ये प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मानकों और पद्धति के अनुरूप थे। यूपीए सरकार की उदारवादी विदेशी निवेश की नीतियों के नाम पर वर्ष 2009 में जब इन भुगतानों पर सीमा समाप्त कर दी गई तो इन मदों के अंतर्गत होने वाले भुगतानों और विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन तेजी से बढ़ने लगे। अब सीमा हटने के बाद विदेशी कंपनियों की भारतीय शाखाओं द्वारा अपनी मूल कंपनियों को रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क भेजने में कोई बाधा नहीं रही और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी स्वीकृति की भी जरूरत नहीं पड़ती। सीमा हटने के बाद रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क के भुगतान तेजी से बढ़ने लगे।

वर्ष 2009 से पहले रॉयल्टी पर सीमा एक समझदारीपूर्ण नीति थी, क्योंकि इसके कारण हमारे चालू खाते पर विदेशी भुगतान घाटा कम रहता था और इसके चलते विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भी कम रहती थी। गौरतलब है कि 2009 से पहले रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क के नाम पर मात्र 4 अरब डालर की विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होता था। लेकिन सीमा हटने के बाद यह भुगतान अभी तक 20 अरब डालर से भी ज्यादा हो गया है।

इस गंभीर परिस्थिति के चलते देश भारी समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि इसके कारण भारतीय करेंसी में लगातार अवमूल्यन हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि विदेशी कंपनियों के कार्याकलापों को अनुशासित किया जाये क्योंकि सीमा हटने के बाद अब वे लगातार रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क के नाम पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर ले जा रहे है। देश में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हेतु जरूरी है कि 2009 से पहले लगी सीमााओं को दुबारा से लगाया जाए, क्योंकि 2009 में किये गये बदलाव को जारी रखने में कोई तर्क नहीं है। रॉयल्टी और प्रौद्योगिकी शुल्क पर लगी रोक से भारतीय कंपनियों, खासतौर पर ऑटोमोबाईल क्षेत्र की कंपनियों के न केवल लाभ बढ़ेंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही गिरावट को भी रोका जा सकेगा। साथ ही साथ छोटे शेयर हॉल्डरों के हितों की भी सुरक्षा इसके साथ होगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

विराट, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी दत्तोपंत ठेंगड़ी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज पर नजर बनाये रखने के लिए संगठनों का मजबूत होना जरूरी होता है। संघ प्रमुख ने मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार में हालांकि अच्छे लोग है लेकिन सरकार की अपनी व्यवस्था होती है जिसके कई बार जनविरोधी होने की भी आशंका बनी रहती है, पर विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठनों को सरकार पर निर्भरता कम कर अपनी मजबूती के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए।

संघ प्रमुख ने मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार में हालांकि अच्छे लोग है लेकिन सरकार की अपनी व्यवस्था होती है जिसके कई बार जनविरोधी होने की भी आशंका बनी रहती है, पर विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठनों को सरकार पर निर्भरता कम कर अपनी मजबूती के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए।

– **स्वदेशी संवाद**

उक्त बातें संघ के सरसंघचालक ने स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में 10 नवंबर 2018 को डॉ. भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ व स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्मदिवस पर आयोजित 'स्मृति व्याख्यान माला' के दौरान कही। राष्ट्रऋषि ठेंगड़ी जी के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहा कि वे न तो अंध आस्तिक थे, न तो कट्टर नास्तिक थे, बल्कि पूरा का पूरा वास्तविक थे। चारों पुरूषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की तरह व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि व दृष्टि के धनी थे। उनका नजरिया वैश्विक था। उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी जी किसी खास के लिए नहीं बने थे। उनकी पहुंच हर जगह थी। भविष्य की दृष्टि इतनी पैनी थी कि आने वाले दिनों में न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना किस करवट बैठेगी, वे सहज ही भांप लेते थे। कभी दो धुरी में बंटी दुनिया में जब शीत युद्ध समाप्त हो रहा था तभी ठेंगड़ी जी ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि दुनिया से लाल झंडे की विदाई का समय करीब आ गया है और हुआ भी वहीं।

संघ के सरसंघचालक ने कहा कि गुरू गोलवलकर जी ने संघ के विचारों की जो अवधारणाएं तय की उसे बाद में पं. दीनदयाल उपाध्याय ने प्रतिपादित किया। इन दोनों महापुरूषों के विचारों को प्रयोग कर जमीन पर उतारने का काम ठेंगड़ी जी ने किया। यह जीवन के हर क्षेत्र में दिखा। ठेंगड़ी जी ने विचारों की राजनीति को महत्व दिया, वहीं मजदूर संगठन खड़ा कर उसके जरिये संघ के विचारों का प्रयोग किया। उन्होंने नारा दिया था कि

'देश के लिए करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम'। यह मंत्र की तरह मजदूरों में फैला। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों के मजदूरों ने इस महामंत्र को अपनी कार्यप्रणाली में शामिल कर मजदूर हितों की आवाज बुलंद की।

सरसंघचालक ने कहा कि ठेंगड़ी जी किसी भी काम में तत्कालीन हित की परवाह नहीं करते थे। हमेशा दूर का रास्ता अख्तियार करते थे। उनका मानना था कि विचारों को प्रयोग करते समय जितने बार और जितने तरह से साधा जायेगा, उसमें संपूर्णता आयेगी। प्रारंभ में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी काम किया था। इसी प्रकार प्रारंभिक दिनों में उनका झुकाव वामपंथ की ओर भी था। वे मार्क्स को बहुत बारीकी से पढ़े और समझे भी थे। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं कि ठेंगड़ी जी को जहां जो कुछ भी अच्छा मिला वे उसे ग्रहण करते गये। यही कारण है कि उनके द्वारा लिखी गई कालजयी पुस्तकों में वेद की ऋचाएं, सुभाषितानि के श्लोक, महापुरूषों के कथ्य के साथ पैगंबर मोहम्मद साहब, महात्मा बुद्ध आदि की कहानियां भी खास अवसर पर आती रही है। उन्होंने नक्सली नेता चारू मजूमदार को भी कोट किया है तो खलील जिब्रान की कहानियों का भी उदाहरण दिया है। ठेंगड़ी जी के विचार किसी विचारधारा के विरोध में नहीं, बल्कि ठीक से देखें तो उनके विचार पूरक लगते है। यही कारण है कि बदलती दुनिया में आज ठेंगड़ी जी के विचार सबसे अधिक प्रासंगिक है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पड़ौसी देश चीन के मजदूर संगठनों ने आज पूरा का पूरा ठेंगड़ी जी के दर्शन पर भरोसा जता रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि ठेंगड़ी जी समाज के सभी वर्गों को एक समावेशी दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि में मजदूर, किसान, छात्र, कलाकार आदि सबको पर्याप्त अवसर देने की बात दिखाई देती है। उन्होंने सबका समर्थन किया। भले ही वह विरोधी ही क्यों न हो। सरसंघचालक ने कहा कि भारत एक शाश्वत, सनातन परंपरा वाला देश है और प्राकृतिक तौर पर इसका ताना–बाना सहकार का है। उन्होंने कहा कि कला का संवर्धन जरूरी है, लेकिन अगर हम पाश्चात्य की नकल छोड़ स्वयं की कला पर जोर देंगे तो इसका भरपूर विकास होगा, दुनिया में देश का नाम होगा और यही काम ठेंगड़ी जी अपने विचारों से, अपने प्रयोगों से कर रहे थे। ठेंगड़ी जी की पुस्तक 'थर्ड–वे' का जिक्र करते हुए सरसंघचालक ने कहा कि दुनिया में किसी भी कार्य को करने के लिए दो रास्ते होते है, पर ठेंगड़ी जी ने बताया कि नहीं एक मध्य मार्ग का एक तीसरा रास्ता भी है तो दोनों भटके हुए को जोड़कर मंजिल तक पहुंच सकता है।

इससे पूर्व स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक श्री सरोज मित्र ने ठेंगड़ी जी को याद करते हुए कहा कि 1968 में मैं उनके साथ जुड़ने के बाद लगातार उनके संपर्क में रहा। ठेंगड़ी जी अच्छे विचारक, लेखक, संगठनकर्ता तथा अनाशक्त योग के सिद्ध पुरूष थे। इंदिरा सरकार के पतन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे त्यागी थे, इसलिए उन्होंने सरकार में कोई पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पुरस्कार भी लेने से मना कर दिया था।

लगभग दो घंटे तक चले कार्यक्रम का संचालन दिल्ली व हरियाणा प्रांत संगठक श्री कमलजीत ने किया। मंच पर सरसंघचालक के अलावा श्री अरूण ओझा, श्री सरोज मित्र, श्री कश्मीरी लाल भी उपस्थित रहें। कार्यक्रम के दौरान कलकता से आये अशोक पाल चौधरी ने ठेंगड़ी जी का पंसदीदा गीत प्रस्तुत किया। बंदेमातरम से पूर्व दिल्ली प्रांत के संयोजक श्री सुशील पांचाल ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। ❑❑

विश्व-व्यापी कार्यक्रम की घोषणा

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी की जन्मशताब्दी (10 नवंबर 2020) वर्ष पर स्वदेशी जागरण मंच देश–दुनिया में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस दौरान वर्ष भर मंच के कार्यकर्ता दुनिया के सभी हिस्सों में कार्यशालाएं, गोष्ठियां, सेमिनार, जागरूकता अभियान, स्वदेशी कार्यक्रम चलाकर पूंजीवाद और साम्यवाद से इतर ठेंगड़ी जी के तीसरे विकल्प के विचारों को जन–जन तक पहुंचायेंगे। उक्त घोषणा आज यहां स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री अरूण ओझा ने ठेंगड़ी जी के जन्मदिवस पर डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित स्मृति व्याख्यान माला के दौरान अपनी बात रखते हुए की। उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी जी एक जुग प्रवर्तक थे। संगठन को खड़ा करने, संगठित लोगों को दिशा देने में उनका कोई मुकाबला नहीं था।

श्री ओझा ने ठेंगड़ी जी की राजनैतिक समझ और परख की चर्चा करते हुए कहा कि एक बार ठेंगड़ी जी पटना आये हुए थे, उन दिनों पटना में सीपीआईएमएल का जोर था। वे लोग व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए थे। ठेंगड़ी जी ने मुझसे कहा कि क्या हमें उनका साहित्य पढ़ने को मिल सकता है? मैंने उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया। इस बीच ठेंगड़ी जी को पता चला कि एमएल के 6 विधायक चुनाव जीते है। वापसी के समय मैं ठेंगड़ी जी से पूछा कि किताबें किस पते पर भेज दूं, तो उन्होंने साफ मना किया और कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने पूछा कि अभी तो आप मांग रहे थे, उन्होंने हंसकर कहा कि अब मुझे उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वे चुनावी राजनीति में जब शामिल हो गये तो उनसे परिवर्तन की उम्मीद करना बेमानी है। ❑

संघ विचार के महान भाष्यकार थे दत्तोपंत ठेंगड़ी

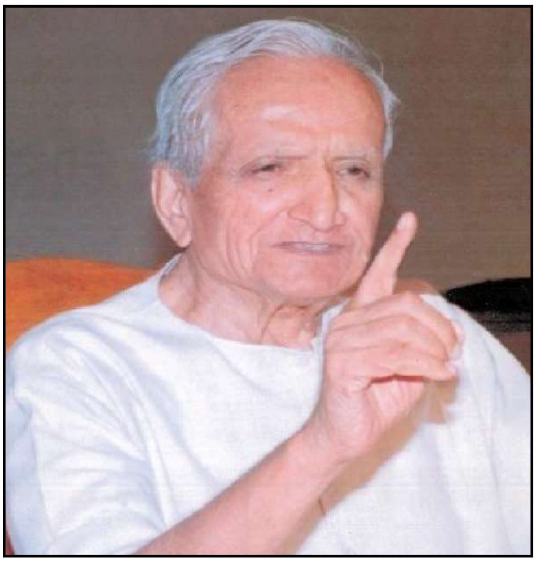

श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी से संबंध सिर्फ संघ के संबंध में ही मेरा ज्यादा है, अपवादात्मक रुप से कई बार उनसे मिलने के लिये गया हूँ। दत्तोपंत जी का जीवन देखकर, उनके चाल–चलन, रहन–सहन, बोलने का ढ़ंग, ये सारा और इसका अनुभव लेकर, प्रष्नों के संबंध में उत्तर देने का उनका जो अद्भुत बौद्धिक सामर्थ्य था, उससे प्रभावित होकर, संघ में जो अनेक कार्यकर्ता, अपने सम्भ्रम को त्यागकर, जो संघ कार्य में रत हुये, जिनके कारण से जो हजारों कार्यकर्ता खड़े हुये, उसमें से मैं भी एक साधारण स्वयंसेवक हूँ। संघ प्रारंभ तो हुआ पच्चीस (25) में, सारी जो पहली पीढ़ी थी संघ की, वह तो, जो प्राथमिक संकल्पना है, यह एक देष है, एक राष्ट्र है, और वह हिन्दू राष्ट्र है। इस बात को समाज में बिठाने के लिए एक पीढ़ी चली गई। वैचारिक दृष्टि से उस समय हिन्दू शब्द के साथ ही एलर्जी थी, स्वातंत्र्य संग्राम चल रहा था, उसके जो आषय है तात्विक उससे कुछ भिन्न और हिन्दू समाज की विचित्र परिस्थिति है, यह संगठित होने वाला समाज है क्या? इन सारी बातों के बीच में संघ की बात को वहाँ पर बिठाना एक पीढ़ी का काम हो गया। बाद में जैसे–जैसे समय बदलता गया, अनेक प्रकार के प्रष्न खड़े होते चले, जो प्रारम्भिक काल में नहीं थे। डॉ. हेडगेवार को कई प्रष्न पूछते तो वो कहते थे मुझे क्या मालूम उनसे पूछो, वो इतिहासकारों से पूछो, तत्व–ज्ञानी से पूछो वह टालते थे, उत्तर नहीं देते थे। हिन्दू शब्द को डिफाईन करने से भी उन्होंने इंकार किया जो अत्यंत प्राथमिक बात है। क्योंकि उन्होंने जानबूझकर किया था वैसा।

लेकिन जैसे–जैसे दिन चले, काम का विस्तार होता चला गया। परिस्थितियों में बदलाव आया, इसलिए अनेक प्रकार के जो प्रष्न, खड़े होते गये, इन प्रष्नों को शास्त्रीय ढ़ंग से, संघ की अत्यंत बुनियादी बातों से सुसंगत, अत्यन्त वैज्ञानिक दृष्टि से सम्मत ऐसी उसकी व्याख्या करना, उसको प्रस्तुत करना, दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, समर्थ भाषा में प्रस्तुत करना, ऐसे एक महान भाष्यकार थे, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी। "द ग्रेटेस्ट कॉमेंटेटर ऑफ संघ आयडियोलोजिकल डायमेन्सनस", संघ के सारे विचार–विश्व को विकसित करना, विकसित हुए आयाम का विषलेण करना और सबके सामने उसको प्रस्तुत कर, उसको सर्व–स्वीकार्य बनाना। यह जो कई लोगों ने काम किया, बड़े महत्व का काम, बड़ा बुनियादी काम, इसमें दत्तोपंत जी का बहुत बड़ा स्थान है। मेरा खुद का एक अनुभव है। मैंने पूछा कि भाषण में वो कई बार बोलते थे, संघ अलग, समाज अलग ऐसा नहीं होना चाहिये और संघ समाज एक ही है। ऐसा कुछ बोलते थे। बोलने में सुनने में तो ठीक ही लगता था, लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? तो उनका जो उत्तर देने का जो ढ़ंग था, "नहीं ऐसा नहीं, कल का इतिहासकार अगर लिखता है, संघ के बारे में कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन था उसने हिन्दू समाज के उपर जितनी–जितनी आपत्तियां थी, उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया। ऐसा यदि लिखने की नोबत आ जाये तो हमारे लिये यह हमारे विचार का पराभव हो गया। और कल का इतिहासकार ऐसा लिखता है कि हिन्दू समाज में ऐसे प्रष्न तैयार हो गये, ऐसी–ऐसी समस्याएं, चुनौतियां खड़ी हो गयी, और उनसे निपटने के लिये हिन्दू समाज के अंतर्गत विचार हुआ, और हिन्दू समाज के विचारवान्–विवेकवान् लोगों ने अपनी बुद्धि लगायी और उन्होंने अपने सामर्थ्य से इसके उत्तर को ढूंढ़ निकाला और हिन्दू समाज स्व–संरक्षण–क्षम बना। हिन्दू समाज ने अपनी समस्याओं को स्वयं हल किया, ऐसा अगर इतिहासकार ने लिखा तो संघ के विचार की विजय होगी, नहीं तो संघ ने प्रोटेक्ट किया ऐसा हो गया, ऐसा नहीं आना चाहिये इसलिये हमारा

संघ के सारे विचार–विश्व को विकसित करना, विकसित हुए आयाम का विश्लेण करना और सबके सामने उसको प्रस्तुत कर, उसको सर्व–स्वीकार्य बनाने में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

– डॉ. श्रीपति शास्त्री

जो संघ का जो एचीवमेंट है उसका रिकार्ड मत मेंटेन करो, बैंक खाते में सारा रिकार्ड हिन्दू सोसाइटी के क्रेडिट पर करना, "ओल दी अचीवमेंट ओफ संघ सुड बी क्रेडिटेड इन दी नेम ओफ हिन्दू सोसाइटी" ऐसे इसको रखना चाहिये और इसके योग्य शब्द वे गढ़ते चले, संघ और समाज समव्याप्त है, संघ और समाज 'को–एक्सटेन्सिव'।

नये–नये संगठन, नये–नये आंदोलन जो कभी–कभी प्रारंभ किये गये, होते चले गये और अभी भी हो रहे है, उसको उन्होंने, यह नई बात आ गई है, ऐसा नहीं बोलते थे। कहते थे यह पहले से संघ विचार में है, डॉ. साहब के समय का एकाध उदाहरण भी देकर। कलकत्ता में जब गड़बड़ हो गई तब डॉ. हेडगेवार ने क्या–क्या किया था उसका उदाहरण देकर, यह प्रारम्भिक काल से निहित संघ विचार है। उसको उन्होंने एक नया शब्द भी दिया 'प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट ओफ संघ आयडियोलोजी" ऐसा उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया। ऐसे वैचारिक दृष्टि से एक संकल्पना के साथ उसको शुरु करना इतना ही नहीं तो सबको समझ में आ सके ऐसे शब्दों में रखकर, संघ के विचार की जो पूंजी है, उसको समृद्ध बनाने वाले एक बहुत बड़े भाष्यकार श्रीमान दत्तोपंत जी ठेंगड़ी हमारे बीच में, अपनी आंखों के सामने ही जीवन जीकर, वो चले गये। इसलिए संघ की वैचारिक भूमिका का जब हम विष्लेषण करने बैठते है, तो कौन सा भी विषय लो, वहाँ पर दत्तोपंत जी का प्रवास आता है। वो आते है, उनका क्या कहना था, बोलने के लिए आते है।

कैसे–कैसे प्रष्न आते चले गये? परिस्थिति जैसे बदलती चली गई, नये–नये प्रष्न आते गये। नये–नये प्रष्न जो संघ के लोगों को भी शायद हजम नहीं हो ऐसे है। दत्तोपंत जी ने एक घटना बतायी थी, 1960 की बात है, 1960 में अपने देष में गृहमंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा थे, उस समय एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया, वामपंथी लोगों से प्रेरित स्टंप ऐसे होते थे वो बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया और स्ट्राइक होने के बाद नुकसान इत्यादि होते है वो हो गया, इसलिए नन्दा जी बहुत नाराज हो गये और उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि एक नया बिल लायेंगे, जिसमें यह स्टम्प करने का माने स्ट्राइक करने का यह जो राइट है, इसको हम ले लेंगे। समस्या समाधान के लिये नया मेकेनिज्म ढूंढेंगे। राइट टू स्ट्राइक यह नहीं रहना चाहिये ऐसा उनका स्टेटमेंट था उस समय। यह स्टेटमेंट आने के बाद 60–61 की बात होगी उस समय एक दो दिन नागपुर में होने के कारण श्रीगुरुजी से मुलाकात हो गई, गुरुजी ने दत्तोपंत जी को पूछा कि यह जो नन्दा जी का स्टेटमेंट है, इसके बारे में बी.एम.एस. की क्या भूमिका है? तुम्हारा क्या स्टैंड है? दत्तोपंत जी ने कहा हमारा स्टैंड तो कुछ नहीं है, गुरुजी ने पूछा की वृतपत्र में तुमने तुम्हारा स्टैण्ड विस्तृत नहीं किया? दत्तोपंत जी ने कहा कि हमको कौन पूछेगा हम इतने छोटे है, कि नगण्य है, इसलिये हम दें तो क्या, नहीं दें तो क्या? दें तो छापें भी नहीं पेपर वाले हमको, हम इतने छोटे है, ऐसा दत्तोपंत जी ने कहा। गुरुजी ने कहा कि वे छापे या न छापे कम से कम अपने पत्र तो छापेंगे, अपनी जो साप्ताहिक है वह तो जरुर छापेंगे, शायद हेडलाईन में भी छापे लेकिन तुम्हारी भूमिका क्या है, यह तो स्पष्ट होनी चाहिये, स्वयंसेवकों को समझना चाहिये, तुम्हारे विचार की दिषा तो समझनी चाहिये, दत्तोपंत जी ने कहा कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि शाखा होने के बाद शाम को फिर मिलेंगे। शाम को चाय के समय मिले, गुरुजी ने पूछा क्या तुम्हारा स्टेटमेंट तैयार हो गया? इन्होंने कहा नहीं, शब्द सूझते नहीं है, क्या कहना। गुरुजी ने कहा अच्छा पेपर और पेन लाओ और गुरुजी ने डिटेक्ट किया उनका जो स्टेटमेंट है बी.एम.एस. का, स्ट्राइक के बारे में, वो उन्होंने डिक्टेट किया, और दत्तोपंत जी ने वो लिख लिया, लिखने के बाद पेपर में भेजा, वो छपकर भी आ गया बी.एम.एस का स्टेण्ड क्या है? वो छपकर आ गया सारा, अर्थात् दत्तोपंत जी के नाम से आ गया, वो ही उसके प्रमुख थे, बाकि लोगों को कुछ मालूम नहीं है। बाद में जो बैठक हुई उस बैठक में अपने ही, अनेक संघ के जो प्रमुख थे, जिनमें कई लोग जिनका कारखानों के साथ संबंध भी था, कई लोग एक्जीट्यूव भी होगें, उन्होंने गुरुजी से षिकायत की, कि हमारे संघ के बहुत बड़े अच्छे प्रचारको को हम अन्य क्षैत्र में काम करने को कहते है, देखा ठेंगड़ी जी जैसे ऐसे बड़े कार्यकर्ता क्या स्टेटमेंट देते है, स्ट्राइक पर।

माने स्ट्राइक करना यह कम्युनिस्टों का धंधा, और उसको रोकना हमारे कार्यकर्ता का देषभक्तिपूर्ण कार्य है, ऐसा एक इक्वेषन है अनेक लोगों के दिमाग में, उन्होंने गुरुजी से षिकायत की। देखीये गुरुजी क्या स्टेटमेंट दिया है, दत्तोपंत जी ने, वही स्टेटमेंट उन्होंने गुरुजी को सुनाया। स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट यह था कि "राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट, देट मीन्स राइट नोट टू वर्क्स इज आलसो ए फन्डामेंटल राइट" इसलिये स्ट्राइक करना यह कामगारों का जो मूलभूत अधिकार है उसको खींच लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। "दे मस्ट हेव देट राइट" यह मैंने सक्षिप्त में कहा लम्बा स्टेटमेंट है, उसका कॉपी है मेरे पास, मैंने दत्तोपंत जी से पूछा, उस समय गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, आंखों के ऊपर ऐसा हाथ रखकर बैठे थे, सबकी सुनते थे, उस समय भी नहीं कहा, बाद में भी नहीं कहा, फिर आपने क्या किया?

उन्होंने कहा कि मैं क्या, कुछ न कुछ बोलना ही चाहिये वो तो बोल रहे है इतना बोल रहे है यह कुछ भी नहीं बोल रहे है तो मैंने कहा देखो भाई यह काम करने के लिये आपने मुझे कहा है, मैं काम कर रहा हूं और इस प्रष्न के ऊपर उचित ऐसा समझा मैंने वह स्टेटमेंट दे दिया, मुझे जो ठीक लगा, आप सब लोग विचार करके अगर ऐसा कहते है कि यह उचित नहीं है, ऐसा यदि निष्चय हो गया तो मैं मेरी गलती हो गई ऐसा मानकर उसको वापिस ले लूगां। इतना कहकर वो भी छूट गये, सब छूट गये उस समय, इस अवस्था से अपने लेबर मूव्हमेंट का काम दत्तोपंत जी कर रहे थे, उस समय यह अपने ही कार्यकर्ताओं की स्थिति थी। ...

(शेष भाग अगले अंक में...)

इज ऑफ डूईंग बिजनेस में भारत की ऊंची छलांग

नहीं है भारत में आर्थिक संकट

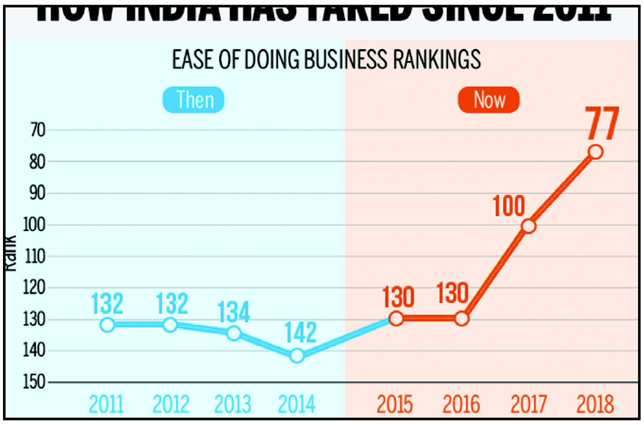

अक्टूबर 31 को विष्व बैंक की रपट के अनुसार 190 देषों में भारत 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' में 23 अंक बढ़ता हुआ 100वें स्थान से 77वें पायदान पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि 2014 से अभी तक यह 142वें पायेदान से 77वें स्थान पर पहुंच चुका है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह खबर भारत सरकार को राहत पहुंचाने वाली है, क्योंकि वर्ष 2018 के प्रारंभ से अभी तक भारतीय रूपया 20 प्रतिषत गिरकर अभी तक 73.54 रूपए प्रति डालर तक पहुंच गया है। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और पिछले दो महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बेतहाषा वृद्धि हुई। हालांकि पिछले 12 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट भी दर्ज हुई। देष का चालू खाते पर विदेषी भुगतान घाटा जो वर्ष 2017—18 में जीडीपी के 1.9 प्रतिषत ही था, चालू वित्तीय वर्ष में 2.6 प्रतिषत तक भी पहुंच सकता है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक अगस्त माह में अपने अधिकतम स्तर 38896.6 से घटकर अक्टूबर 11,2018 तक मात्र 34000 तक पहुंच चुका है। इन परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पुनः एक बार आर्थिक संकट में आ गया है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2011—12 और 2012—13 में चालू खाते पर विदेषी भुगतान घाटा जीडीपी के 4 प्रतिषत से भी ज्यादा हो गया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी काफी ऊंची थी और रूपया भी इस दौरान कमजोर हो रहा था। गौरतलब है कि 28 अगस्त 2013 को भारतीय रूपया उस समय के सबसे अधिक कमजोर स्तर 68.84 रूपए प्रति डालर पर पहुंच गया था।

प्रष्न यह उठता है कि क्या भारत पुनः उसी प्रकार के संकट में आ पहुंचा है, जैसे वह 2012—13 में पहुंच गया था। लेकिन यदि देखा जाए तो उस समय की आर्थिक परिस्थितियां वास्तव में गंभीर थी। आज की परिस्थिति उस समय से काफी भिन्न है।

— डॉ. अश्वनी महाजन

अब प्रष्न यह उठता है कि क्या भारत पुनः उसी प्रकार के संकट में आ पहुंचा है, जैसे वह 2012—13 में पहुंच गया था। लेकिन यदि देखा जाए तो उस समय की आर्थिक परिस्थितियां वास्तव में गंभीर थी। आज की परिस्थिति उस समय से काफी भिन्न है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 8 प्रतिषत औसत जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले 2011—12 और 2012—13 में जीडीपी की वृद्धि दर क्रमषः 6.2 प्रतिषत और 4.2 प्रतिषत तक पहुंच गई थी। जबकि वर्ष 2017—18 में जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिषत रही और 2018—19 के लिए इसके 7.8 प्रतिषत तक पहुंचने की आषा है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बता रही हैं। यही नहीं 2012 और 2013 में महंगाई दर भी दो अंक में पहुंच गई थी, जो आज 3.5 प्रतिषत के आसपास है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हालांकि भारतीय रूपए पर संकट बरकरार है और पेट्रोल और डीजल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत मुकाम पर है।

औद्योगिक और कृषि विकास

पिछले 3—4 वर्षों में जीडीपी की वृद्धि दर ही नहीं बढ़ी है, बल्कि हर क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2012—13 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1.1 प्रतिषत बढ़ा, जबकि 2013—14 में वह 0.1 प्रतिषत घट गया। लेकिन उसके बाद उसमें

लगातार वृद्धि का रूख दिखाई दे रहा है और ताजा आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2017 और अगस्त 2018 के बीच यह 5. 2 प्रतिषत बढ़ा। इसी प्रकार कृषि में भी लगातार प्रगति दिखाई दे रही है, चाहे वो कुल खाद्यान्न हो अथवा उसमें दालों का हिस्सा हो, उसमें भी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 2014–15 में 25.3 मिलियन टन से बढ़कर 2017–18 तक 277.5 मिलियन टन तक पहुंच गया है। उधर दालों और तिलहनों के उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शेष कृषि उत्पाद जैसे कपास, गन्ना इत्यादि का भी उत्पादन अभूतपर्व रूप से बढ़ा है। इसका परिणाम है कि खाद्य मुद्रा स्फीति जो नवंबर 2013 में 14.7 प्रतिषत तक पहुंच गई थी वो जून 2017 तक आते–आते –2.12 प्रतिषत तक आ गई, यानि कीमतें बढ़ने की बजाय घटने लगी। अभी भी खाद्य मुद्रा स्फीति 3 से 4 प्रतिषत के बीच में बनी हुई है। आंकड़े दिखाते हैं कि पेट्रोल, डीजल की कीमतें बेषक बढ़ रही हैं, लेकिन दाल, अनाज, तेल इत्यादि में बहुत ही कम महंगाई हो रही है।

राजकोषीय संतुलन

महंगाई में कमी केवल औद्योगिक और कृषि उत्पादन बढ़ने से ही नहीं, बल्कि राजकोषीय संतुलन से भी संभव हुई है। गौरतलब है कि 2011–12 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.7 प्रतिषत के बराबर था। उसके मुकाबले 2017–18 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के मात्र 3.5 प्रतिषत तक पहुंच गया है। एक तरफ तेजी से बढ़ती जीडीपी और दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे में आ रही कमी ने मांग और पूर्ति में एक बेहतर संतुलन स्थापित किया है, जिसके चलते पेट्रोल–डीजल में महंगाई के बावजूद शेष मंहगाई थमी हुई है।

संकट जैसे हालात नहीं

किसी भी अर्थव्यवस्था में संकट तब माना जाता है जब देष में बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल नही होता, उत्पादन और आमदनी में ठहराव आ जाता है, महंगाई बढ़ती है अथवा विदेषी भुगतान में संकट होता है।

दुनिया के कई मुल्क इस समय विदेषी कर्ज के संकट में हैं। लेकिन भारत के विदेषी मुद्रा भंडार पिछले 4 सालों में लगभग 25 प्रतिषत बढ़ चुके है। अपनी आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेषों पर आश्रित हैं और उनकी सरकारें सामाजिक सुरक्षा और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। औद्यागिक उत्पादन बढ़ रहा है, देष के खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं और यही नहीं देष भारी मात्रा में कृषि वस्तुओं का निर्यात भी कर रहा है। सरकार का बजट पूरी तरह से नियंत्रण में है और प्रत्यक्ष कर हों अथवा अप्रत्यक्ष कर केन्द्र और राज्य सरकारों का राजस्व लगातार बढ़ रहा है।

ऐसे में हालांकि पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय कारणों से देष में डालरों की मांग बढ़ने से रूपए पर दबाव आ रहा है और रूपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, लेकिन इसमें संकट जैसे कोई हालात नहीं। डालरों की मांग बढ़ने के दो प्रमुख कारण दिखाई देते हैं, पहला कारण है, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और दूसरे विदेषी संस्थागत निवेषकों द्वारा निवेष की निकासी। लेकिन इन कारणों का असर बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के वायदा बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ऐसा लगता है कि अब तेल की कीमतें गिरावट का रूख ले लेंगी। विदेषी पोर्टफोलियों निवेषकों ने भारतीय बाजारों में खूब पैसा बनाया है। कुछ अल्पकालिक कारणों से चाहे उन्होंने अपना पैसा भारतीय बाजारों से निकाल है, लेकिन यह लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। उनकी वापिस आने पर डालरों की आपूर्ति फिर से बढ़ जाएगी और रूपया वापिस अपने पुराने स्तर पर आ सकता है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हो या बेहतर जीडीपी, विदेषी मुद्रा भंडार, काबू में मंहगाई सभी संकेत एक बेहतर भविष्य की ओर इंगित कर रहे हैं।

क्या करें कि हालात सुधरे?

क्योंकि यह संकट अल्पकालिक है इसलिए नीति नियंताओं को धैर्य से काम करना होगा। रूपए में गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक विदेषी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करे, यह उचित नीति होगी। यही नहीं विदेषी व्यापार घाटे को भी जल्द पाटने की जरूरत है, उसके लिए गैर जरूरी वस्तुओं के आयातों को टैरिफ बढ़ाकर थामा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य देष जो भारत में बाजार पर कब्जा जमाने के लिए अपना माल यहां डंप कर रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना भी उचित नीति हो सकती है। यही नहीं विदेषी संस्थागत निवेषकों को भी अनुषासित करने की जरूरत है। उनके निवेषों पर 'लॉक इन पीरियड' लगाना और उनके द्वारा राषि को देष से ले जाने से रोकने के लिए 'टोबिन टैक्स' लगाना भी सही नीति होगी।

कई देषों में इस प्रकार के कर की व्यवस्था है, जिसके अनुसार विदेषी निवेषकों पर तब लगाया जाता है, जब वो अपना निवेष बाहर ले जाने के लिए देष की कैरेंसी को डॉलरों में परिवर्तित करते हैं। कहा जा सकता है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जिसमें सभी क्षेत्रों में जीडीपी बढ़ रही है और सभी आर्थिक संकेतक सही दिषा में है, डॉलरों की मांग में अल्पकालिक वृद्धि किसी बड़े संकट का संकेत नहीं देती, लेकिन परिस्थितियों का बेहतर ढंग से प्रबंधन भी जरूरी है। ❑❑

पत्रकारों के खिलाफ हिंसा में दंडमुक्ति के खात्मे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जान को जोखिम में डालकर खबरे लाने वाले पत्रकारों की खबर रखने तथा उन्हें आवश्यक सुरक्षा देने का आह्वान किया है। पत्रकारों के विरूद्ध हिंसा में दंडमुक्ति के खात्मे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (2 नवंबर) पर संघ में महासचिव ने दुनिया के सभी सदस्य देशों से लोकतंत्र को मजबूत करने तथा इसके चौथे खंभे को संरक्षण देने की अपील की है। बीते वर्षों में हुई घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए सलाह दी गई है हि सभी देश ऐसा माहौल तैयार करें ताकि पत्रकार बिना किसी भेदभाव के निर्भीक होकर अपना काम कर सके।

हाल ही में नक्सलियों ने रायपुर के नीलवाया गांव के पास दूरदर्षन के फोटो पत्रकार अच्युतानंद साहू को गोलियों से भून दिया। वहीं रांची के चतरा में पत्रकार चंदन तिवारी को कुछ सिरफिरे बदमाषों ने पीट–पीटकर मार डाला। पत्रकारों के खिलाफ हिंसा में दंडमुक्ति के खात्मे के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (2 नवंबर) के ठीक दो दिन पहले हुई इन वारदातों ने भारत को एक बार फिर प्रेस विरोधी देष के रूप में अगली कतार में खड़ा कर दिया है। प्रेस की आजादी और मानवाधिकार की निगरानी करने वाली (भारत के साथ–साथ दुनिया भर की) संस्थाओं ने इसकी निंदा की है तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर की है तथा कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्यों को परामर्ष जारी कर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देष दिए हैं।

संचार क्रांति के आने और मोबाइल के प्रचार–प्रसार से ख़बरों का प्रकाष में आना आसान हो गया है। सोषल मीडिया के आने से एक अच्छी शुरुआत ये हुयी है कि ख़बरों को प्रसारित करने के अख़बार समूहों और चैनल्स के सीमित स्पेस के बीच आम लोगों को असीमित जगह मिली है। ख़बरें अब देष की सीमाओं की मोहताज नहीं रही हैं। ख़बरों की

पत्रकारों के विरूद्ध हिंसा में दंडमुक्ति के खात्मे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (2 नवंबर) पर संघ में महासचिव ने दुनिया के सभी सदस्य देशों से लोकतंत्र को मजबूत करने तथा इसके चौथे खंभे को संरक्षण देने की अपील की है।

– अनिल तिवारी

भरमार है। मोबाइल ने 'सिटीजन जर्नलिज्म' को बढ़ावा दिया है और आज मोबाइल रिकॉर्डिंग और घटना स्थल का फोटो, ख़बरों की दुनिया में महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की तरह उपयोग में आ रहा है। लेकिन मीडिया की इस विकास यात्रा में, पत्रकारों के जीवन में क्या कोई बदलाव आया है? क्या इनके जीवन की सुरक्षा को लेकर कोई कानून बनाया गया है?

साल 2013 में बाली में कवरेज करने पहुंचे दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या कर दी गयी थी। संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 68वें अधिवेषन के दौरान पत्रकारों की हत्या पर चिंता जताते हुए सदस्यों ने कडी निंदा की तथा दुंनिया के देषों को ऐसी घटनाओं के खिलाफ खडे होने का आहवान किया। अधिवेषन में हर साल दो नवम्बर को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा में दंड मुक्ति की समाप्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का भी ऐलान किया गया।

परंतु सच्चाई यह है कि दुनिया के स्तर पर सबके अधिकारों की बात करने वाले, पत्रकारों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2007 से साल 2017 के दौरान 1042 पत्रकार मारे गए। यानि कि प्रति चार दिन में एक पत्रकार की हत्या होती रही है। दर्ज किए गए मामले में सफलता नही के बराबर रही। मरने वाले पत्रकारों में 93 प्रतिषत स्थानीय रहे जबकि 7 प्रतिषत विदेषी। इसी तरह 94 प्रतिषत पुरूष तो 6 प्रतिषत महिलाएं षिकार हुई। पत्रकारों की हत्या के मामले में अरब के देष आगे रहे। अरब देषों में 34 प्रतिषत जबकि एषिया पेसिफिक में 26 प्रतिषत। लैटिन अमेरिका में 22 प्रतिषत वहीं अफ्रीका में 11 प्रतिषत रहा। सबसे कम हत्याएं नार्थ अमेरिका व पष्चिमी यूरोप में 2 प्रतिषत रही जबकि मध्य व पूर्वी यूरोप में 4 प्रतिषत रही है।

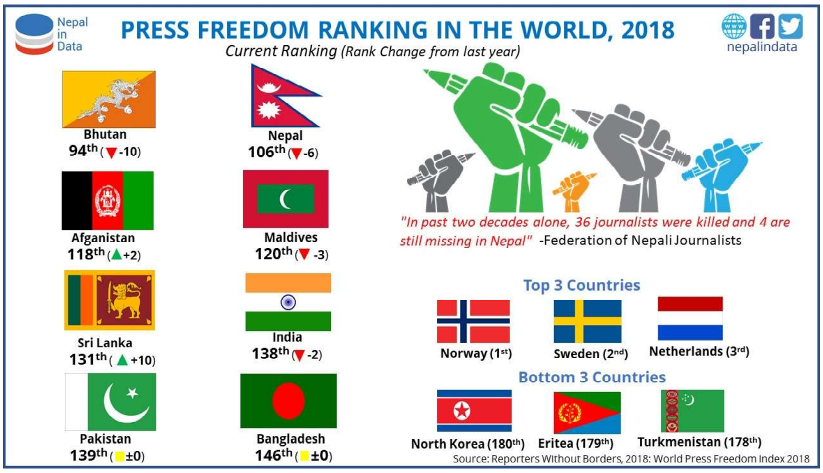

वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत तीन पायदान नीचे खिसककर अब 136 में पर आ गया है।

प्रेस की आजादी के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ताजा रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत तीन पायदान नीचे खिसककर अब 136 में पर आ गया है। हम अपने जुझारू मीडिया को दक्षिण एषिया में सबसे स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन फ्रीडम हाउस की नजर में यह हकीकत में आंषिक रूप से ही स्वतंत्र है। बीते साल भारत में 14 पत्रकारों की हत्या, 46 पर हमले, 127 पत्रकारों के खिलाफ पुलिस उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं।

दरअसल न सिर्फ भारतीय पत्रकारों के लिए बल्कि विश्व के पत्रकारों के लिए यह गुजरता साल दुखद और जानलेवा रहा। दुनिया भर में कुल 100 से ज्यादा पत्रकारों ने अपनी जान गंवा दी। तो आइए जानते हैं कौन सी वो आवजें थी जिन्हें और जिंदा रहना था लेकिन उन्हें सच बोलने के कारण अपनी जान से गवांनी पड़ी।

सीरिया आतंक और गृह युद्ध दोनों से पीड़ित है। इस देष को पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक बताया जाता है। इस साल यहां कुल 12 हत्याएं हुई वहीं मैक्सिको में भी 11 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। मैक्सिको में जिन पत्रकारों की हत्या हुई उनमें जेवियर वालडेज की हत्या सबसे भयानक रही वह ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ लगातार लिख रहे थे जिसके एवज में उन्हें अपनी जान गवांनी पड़ी।

50 वर्षीय इस पत्रकार को बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया। ड्रग्स माफियाओं पर रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने नार्को जर्नलिज्म नामक एक किताब भी लिखी।यह किताब मैक्सिको में ड्रग्स के खिलाफ पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों के लिए एक शब्दकोष साबित हुई। मैक्सिको का हाल यह है कि देष से ज्यादातर पत्रकार या तो देष छोड़ चुके हैं या तो पत्रकारिता का पेषा।रिपोर्टर्स विडाउट बॉर्डर नाम की एक स्वतंत्र संस्था बताती है कि अब वार रिपोर्टिंग से ज्यादा खतरनाक राजनीतिक घोटलों और नियोजित अपराधों की रिपोर्टिंग में है।

फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेरते के हालिया बयानों ने इस देष को पत्रकारों के लिए एषिया का सबसे खतरनाक देष बताया।दुतेरते ने विवादित बयान देते हुए कहा कि आप पत्रकार हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप की हत्या नहीं होगी। इसके बाद

फिलीपींस में लभगभ पांच पत्रकारों की हत्या की गई।यूरेषिया स्थित तुर्की को पत्रकारों की जेल कहा जाता है। यहां 42 रिपोर्टरों को जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। 52 पत्रकारों को जेल की हवा खिला रहा चीन इस सूची में सबसे आगे है। इन सभी के अलावा सीरिया में 24 ईरान में 23 और वियतनाम में 19 पत्रकारों को कैद किया हुआ है।

वहीं भारत में गौरी लंकेष की हत्या ने बातें बनाने वालों को नींद से जगा दिया। लंकेष की हत्या के ठीक 2 दिन बाद सहारा के पंकज मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इंदौर में स्थानीय अखबार 'अग्निबाण' के 45 वर्षीय पत्रकार श्याम शर्मा की हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने उनकी कार को रुकवाकर उनका गला रेंत दिया। इसके 15 दिन बाद 31 मई को हिन्दी दैनिक 'नई दुनिया' के पत्रकार कमलेष जैन की मध्य प्रदेष के पिपलिया मंडी क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अभी इस घटना को 15 दिन ही हुए थे कि एक और पत्रकार की हत्या हो गई। 20 सितंबर को त्रिपुरा में स्थानीय टेलीविजन पत्रकार शांतनु भौमिक की तब हत्या कर दी गई जब वह इंडीजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) तथा त्रिपुरा राजाएर उपजाति गणमुक्ति परिषद (टीआरयूजीपी) के बीच संघर्ष की कवरेज कर रहे थे। भौमिक की हत्या के महज तीन दिन बाद 23 सितंबर को पंजाब के मोहाली में 64 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार केजे सिंह और उनकी 94 वर्षीय मां की हत्या कर दी गई। सिंह के पेट में चाकू से कई वार किए गए थे और उनका गला रेत दिया गया था।उनकी मां की हत्या गला घोंटकर की गई थी। इसके बाद 21 अक्तूबर को उत्तर प्रदेष के गाजीपुर जिले में दैनिक जागरण के पत्रकार राजेष मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनके भाई बुरी तरह घायल हुए थे। हमलावरों ने उन पर कई गोलियां चलाई थीं।

गत 20 नवंबर को बंगाली अखबार स्यांदन पत्रिका के पत्रकार सुदीप दत्ता भौमिक की अगरतला से 20 किलोमीटर दूर आरके नगर में 2–त्रिपुरा राइफल्स के एक कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके 10 दिन बाद 30 नवंबर को उत्तर प्रदेष में कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़े पत्रकार नवीन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

आखिर ऐसा क्यों है कि छोटे शहरों–कस्बों में पत्रकारिता करना लगातार मुष्किल होता जा रहा है? पुलिस, अफसर और राजनेता क्यों पत्रकारों को हिकारत भरी निगाह से देखते हैं? इसके लिए किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इक्का–दुक्का पत्रकारों की रहस्यमयी हत्याएं पहले भी होती थीं, लेकिन अब अक्सर इस तरह की खबरें आने लगी हैं। पहले पत्रकारों के पक्ष में समाज खड़ा रहता था। संपादक स्वयं पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ जाया करते थे। पत्रकार–संगठन हमेषा पीछे खड़े रहते थे। सरकारों के भीतर भी ऐसे लोग हुआ करते थे, जो पत्रकारीय मूल्यों से इत्तिफाक रखते थे। जब भी पत्रकार और पत्रकारिता पर कोई संकट आता, समाज उसके पक्ष में ढाल बनकर खड़ा हो जाता था।

आखिर ऐसा क्यों है कि छोटे शहरों-कस्बों में पत्रकारिता करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है? पुलिस, अफसर और राजनेता क्यों पत्रकारों को हिकारत भरी निगाह से देखते हैं?

लेकिन आज पत्रकार पिट रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। समाज का थोड़ा–सा भी भय होता, तो क्या चंदन को इस तरह से पीट पीट कर यातनाएं दी जातीं? छायाकार साहू तो बस केवल एक तष्वीर खींचना चाह रहे थे, फिर भी इतनी असहिष्णुता? सहिष्णुता लगातार कम क्यों हो रही है? प्रभावषाली गिरोहबंद अथवा सत्ता–केंद्रों में बैठे लोग तनिक भी अपने खिलाफ नहीं सुन सकते। सत्य की दुर्बल से दुर्बल आवाज से भी वे खौफ खाए रहते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई उनकी सच्चाई उजागर कर रहा है, वे उसे निपटाने में लग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि स्थानीय पत्रकारिता में मूल्यों का स्खलन भी कम नहीं हुआ है। पत्रकारिता का अतिषय फैलाव होने से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में 'अयोग्य' उतर आए हैं। उन्हीं की वजह से यह पेषा बदनाम होता जा रहा है। समाज में उसका आदर घटता जा रहा है। इसीलिए अब किसी पत्रकार को पिटता हुआ देखकर कोई बचाने नहीं आता। यह स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बड़े शहरों की बात नहीं कहता, छोटे शहरों–कस्बों में स्थिति हद से बाहर हो रही है। खासकर हिंदीभाषी क्षेत्र में, जबकि यही हिंदी पत्रकारिता की बुनियाद है। इसे बचाया जाना चाहिए।

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले कमेटी फॉर प्रोटक्षन आफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों पर हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ना होने उनके बेदाग छूट जाने के मामले में 100 प्रतिषत वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत दंडमुक्ति रैंकिंग में 13वें पायदान पर है।

प्रेस की आजादी को खतरा इसके शुरुआत से ही रहा है। 1857 की क्रांति के साथ ही लॉर्ड कैनिंग ने एक गैंगिंग एक्ट बनाया था, जिसमें सरकार से

लाइसेंस लेना तथा छपने वाली सामग्री को दिखाना अनिवार्य था। क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों ने 1876–77 में देष में आये अकाल की खबरों को प्रमुखता से छापकर ब्रिटिष सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनकी आलोचनाओं को कुचलने के लिए तब 1876–77 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। बालगंगाधर तिलक को इसी एक्ट के तहत दो बार जेल जाना पड़ा था। सीमित कानूनी संरक्षण के नाम पर प्रेस की आजादी का ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। आईपीसी की धारा 12ए में राष्ट्रद्रोह का प्रयोग, धमकी, मानहानि आदि कई तरह से प्रेस की आजादी को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर नेताओं द्वारा मानहानि का मुकदमा प्रेस पर अंकुष के लिए ही लगाया जाता है। तमिलनाडु में 1991 से 96 के बीच जयललिता सरकार द्वारा प्रेस पर 120 मानहानि के मुकदमे दायर किए गए थे। बोलने की आजादी और इसका विस्तार कहे जाने वाले प्रेस की आजादी निर्बाध होनी चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 19 की उपधारा 2 में मौजूद संवैधानिक प्रावधान प्रेस पर प्रभावी नियंत्रण लगाता है। सरकारी गोपनीयता कानून पत्रकारों को देष की रक्षा से जुड़े मामलों की खबर छापने से रोकता है। हालांकि इसके दुरुपयोग की भी संभावना है।इसके लिए संसद इतना जरूर कर सकती है कि पत्रकारों को आपराधिक कार्रवाई से बचाने के लिए एक कानून बनाए और उन्हें राष्ट्र द्रोह से बचाए।

ग्रीस की संसद द्वारा 2015 में एक ऐसा ही संषोधन किया गया है, जो कि एक अच्छा खाका पेष करता है। इस संषोधित कानून के मुताबिक मानहानि के किसी मामले में अदालत दोनों पक्षों की सामाजिक, आर्थिक हालात के हिसाब से हर्जाना लगायेगी तथा छोटी गलती के सुधार का अवसर भी देती है। अगर इस तरह की व्यवस्था भारत में की जाए तो यहां भी सुधार की संभावना है। नहीं तो मीडिया का नजरिया बदलेगा और आलोचना की प्रवृत्ति को एक तरह से धीरे–धीरे खत्म कर देगा। प्रेस काउंसिल आफ इंडिया को एक अलग कानून एडवोकेट एक्ट जैसा बनाकर इसे और अधिक संपन्न करने की जरूरत है। जिस तरह से वकीलों के लिए देष में बार काउंसिल का निर्माण किया गया है, चिकित्सकों के लिए मेडिकल कौंसिल है उसी तरह से पत्रकारों के लिए भी एक एक्ट बनाना चाहिए। इससे पत्रकारों का दर्जा भी बढ़ेगा और उन्हें अनैतिक व अव्यवसायिक तरीकों से मुक्ति भी मिलेगी। हमें पत्रकारों को व्यापक सुरक्षा देकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए।

पत्रकार की नौकरी जहां असुरक्षा की भावना से घिरी रहती है वहीं पूरी दुनिया के स्तर पर राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है।

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार, 70 प्रतिषत रिपोर्टर/कैमरा मैन, युद्ध और हिंसा की खबर कवर करने के दौरान मारे जाते हैं। साहसिक कार्य के दौरान हुयी हिंसा के षिकार ज़्यादातर पत्रकार किसी एक अख़बार या चैनल्स के नहीं होते हैं। कभी 'स्ट्रिंगर' तो कभी छोटे समूह के लिए काम करने वाले पत्रकारों की मौत के बाद उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अपने देष में भी समय–समय पर पत्रकारों के उत्पीड़न की ख़बरें आती रहती हैं, कई बार घटना की सत्यता आरोप–प्रत्यारोप में दब जाती है।

पत्रकार की नौकरी जहाँ असुरक्षा की भावना से घिरी रहती है वहीं पूरी दुनिया के स्तर पर राजनीतिक और संवेदनषील मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। रिपोर्टिंग के दौरान मारे जाने के साथ साथ, सोषल मीडिया पर उनको गाली और धमकी आम होती जा रही है। महिला पत्रकारों का काम और कठिन हो रहा है। उनके साथ सोषल मीडिया पर गाली और चरित्र हनन की घटनाएं बढ़ रही हैं। पत्रकारिता के प्रमुख सिद्धांतों का पालन, जिसमें निष्पक्षता और सत्य उजागर करना प्रमुख सिद्धांत में से है, चुनौती बनता जा रहा है। ईमानदार पत्रकारिता, इस बदले समय में काफी चुनौतीपूर्ण लग रही है। ये भी सच है कि पत्रकारों में भी एक वर्ग, अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए ख़बरों और अपने रसूख का इस्तेमाल करता है और जनता को गुमराह करता है।

क्या पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अपने अधिकार की आवाज सुनी जाएगी? क्या महिला पत्रकारों को निर्भीक होकर अपना काम करने दिया जायेगा? अपहरण, हत्या, हिंसा का जोखिम लेकर दुनिया भर के पत्रकार तो ख़बरें हमारे बीच लाते हैं लेकिन उनकी खबर कौन लेगा?

कल्पना कीजिए की देष में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अलावा कोई संस्थान न हो। कोई ऐसा तंत्र न हो जो सरकार को उसकी नीतियों के लिए सवालों के कठघरे में खड़ा कर सके। ऐसा होने पर कैसा होगा सरकार निरंकुषता के घोड़े पर सवार जन अकाक्षांओं को कुचलती हुई पूंजीवादियों के गोद में जा बैठेगी। समाज के दबे कुचले वर्ग को कोई संभालने वाला नहीं होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकतंत्र के चौथे खंभे की मजबूती और बेहतरी की कायल रही है। सरकार ने मीडिया पर हो रहे हमलों से निपटने तथा दोषियों को सजा दिलाने के लिए कडा कदम उठाने का निर्देष भी जारी किया है।❑❑

सूखा या बाढ़ नहीं, किसान की त्रासदी है माटी मोल कीमतें

जब बाजार में कीमतें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की आधी रह जाएं तो आपको क्या लगता है किसानों को क्या करना चाहिए? जब बाजार मूल्य लागत से भी कम हो जाएं तो किसानों को क्या करना चाहिए? ये वे सवाल हैं, जिनका सामना किसान पिछले चार दषकों से करते आ रहे हैं। इन सवालों का जवाब अभी तक कोई नहीं खोज पाया है, न कृषि अर्थषास्त्री न नीति निर्माता। अधकचरी योजनाओं और वादों के अलावा इस सवाल को बड़ी चतुराई से नजरअंदाज किया जाता रहा है, बिना यह अहसास किए कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य चुकाना किसान और उसके परिवार के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है।

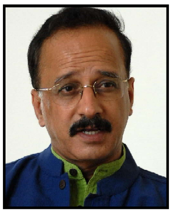

सड़कों पर टमाटर फेंके जाने की खबरें आने लगी हैं, इस बीच मंडी में आने वाली हर ताजा सब्जी की कीमत बहुत कम हो गई है। जब फसल कटाई के बाद उपज माटी के मोल बिकने लगे तो किसान के पास आत्महत्या करने या फिर खेती छोड़कर शहरों में छोटामोटा रोजगार खोजने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता।

– देविन्दर शर्मा

उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5600 रुपए प्रति क्विंटल है लेकिन राजस्थान की कोटा मंडी में किसानों को एक क्विंटल उड़द की अधिकतम कीमत महज 2000 रुपए मिल रही है। एक क्विंटल उड़द उगाने की लागत लगभग 3428 रुपए आती है। एक स्थानीय अखबार ने अनुमान लगाया है कि इस तरह किसानों को हर दिन लगभग 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी तरह पंजाब में किसानों को मक्के का दाम प्रति क्विंटल 1100 से ज्यादा नहीं मिल रहा है। इस साल मक्के के लिए जो 1700 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी घोषित हुआ है यह उससे 35 प्रतिषत कम है। इस एमएसपी में ए2+एफएल लागत भी जुड़ी हुई है।

फिलहाल, सड़कों पर टमाटर फेंके जाने की खबरें आने लगी हैं, इस बीच मंडी में आने वाली हर ताजा सब्जी की कीमत बहुत कम हो गई है। जब फसल कटाई के बाद उपज माटी के मोल बिकने लगे तो किसान के पास आत्महत्या करने या फिर खेती छोड़कर शहरों में छोटामोटा रोजगार खोजने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। इसमें कोई हैरानी बात नहीं है कि अकेले जून महीने में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में ही 208 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। दूसरी जगहों पर भी किसानों के खेतों में मौत का नाच बेरोकटोक जारी है।

खेती के मामलों के जानकार और शोधकर्ता रमनदीप सिंह मान ने कीमतों में हाल में आई गिरावट का एक चार्ट तैयार किया है। अभी तो फसल कटने की शुरूआत भर हुई है और देष भर में पहले ही कीमतें मुंह के बल गिर चुकी हैं। देखिए किसानों को एमएसपी की तुलना में उनकी उपज की क्या कीमत मिल रही है :–

- **उड़दः** कोटा (राजस्थान) में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि इसका एमएसपी 5600 रुपए प्रति क्विंटल है।
- **मक्काः** मंदसौर (मध्य प्रदेष) में 1300 रुपए प्रति क्विंटल और पंजाब में 1075 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि इसका एमएसपी 1700 रुपए प्रति क्विंटल है।

- **मूंग**ः गंगानगर (राज.) में 5000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि इसका एमएसपी 6975 रुपए प्रति क्विंटल है।
- **सोयाबीन**ः हर्दा (मध्य प्रदेष) में 2800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि इसका एमएसपी 3399 रुपए प्रति क्विंटल है
- **कपास**ः धामनोद (मध्य प्रदेष) में 4600 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि इसका एमएसपी 5450 रुपए प्रति क्विंटल है।

लगातार तीन साल से फसल कटाई के समय पर फसलों के दाम बुरी तरह से गिरे हैं। अब आप किसानों की दुर्दषा और उनकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। साल दर साल किसान मेहनत करते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ खेतों में काम करते हैं और मंडी पहुंचने पर पता चलता है कि उनकी उपज के दाम तो मिट्टी में मिल चुके हैं। अपने पूरे परिवार के साथ की गई मेहनत के बदले उसे घाटा नसीब होता है जो अंततः उसे अपनी जीवनलीला खत्म कर देने पर विवष कर देता है। अब कल्पना कीजिए, लगातार तीन बरसों से घाटा सह रहे किसानों की हालत का। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, खेतों पर मौत का भयानक नाच जारी है।

किसी बरस पड़े सूखे या उस साल हुई भारी बारिष को तबाही कहना गलत है। ये सब चीजें तो सामान्य बातें हैं पर शायद किसान के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है मंडी में उपज की कीमतों में आने वाली जबर्दस्त गिरावट। कुछ साल पहले विश्व त्रासदी रिपोर्ट को दिए गए साक्षात्कार में मैंने कहा था, "किसान महज चक्रवात या बाढ़ की त्रासदी नहीं झेलता। सूखे या भयानक बारिष के लिए तो किसान काफी कुछ तैयार रहता है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा सदमा तो तब लगता है जब अनुकूल मौसम और भरपूर फसल होने के बाद भी बाजार में उसकी उपज को वाजिब दाम नहीं मिलते। यह ज्यादा बड़ी त्रासदी है।" खेती की सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हर बार जब भी किसान फसल की बुआई करता है, उसे इस बात का अहसास तक नहीं होता कि दरअसल वह घाटे की फसल बो रहा है।

हाल ही में शुरू की गई PM AASHA स्कीम में भी सरकार ने साफ किया है कि केवल विपणन योग्य 25 पर्सेंट अधिषेष फसल की ही सरकारी खरीद होगी। खाद्य पदार्थों का बफर स्टॉक बनाने के लिए इतना पर्याप्त है। पर बड़ा सवाल है कि बाकी की 75 प्रतिषत उपज का क्या होगा? अगर किसान कम कीमत पर अपनी फसल बेचता है तो उसे हुए नुकसान की भरपाई कहां से होगी?

ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार की निगाह में खेती आर्थिक गतिविधि है ही नहीं। बाजार सुधार का पूरा ढांचा खेती के दोहन पर टिका है जिसमें खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों को महज जनता का पेट भरने और उद्योग को सस्ता व कच्चा माल मुहैया कराने का जरिया माना जाता है। कच्चा माल जितना सस्ता होगा उसे उपलब्ध कराने वाले नाकारा बाजार की उतनी ही ज्यादा तारीफ होगी। जो बाजार किसानों का जितना अधिक शोषण करते हैं व उतने ही अधिक सक्षम माने जाते हैं। इस लिहाज से eNAM और कुछ नहीं शोषण करने वाले बाजार का उन्नत डिजाइन भर है। इसमें व्यापारियों को सस्ती दर पर माल मिल जाता है लेकिन किसानों से उनकी उपज खरीद मूल्य पर नहीं खरीदी जाती और इस तरह उनका मुनाफा मारा जाता है।

सबसे बेहतर विकल्प यह है कि वर्तमान में मौजूद कृषि मूल्य एवं लागत आयोग (सीएसीपी) का पुनर्गठन किया जाए। सीएसीपी इस समय अलग–अलग फसलों के लिए एमएसपी तय करता है। इसका नाम बदलकर कृषक आय एवं कल्याण आयोग कर देना चाहिए जिसका काम कृषक परिवार की न्यूनतम आय तय करना और उसे प्राप्त करने के तरीकों का सुझाव देना हो। अगर हम किसान की न्यूनतम आय को सबसे निचले दर्जे के कर्मचारी की न्यूनतम आय यानि 18,000 रुपए प्रति माह भी मानें तो आयोग का काम किसी क्षेत्र विषेष में रहने वाले किसानों की औसत आय की गणना करने और न्यूनतम आय से उसके अंतर को इनकम ट्रांसफर के जरिए किसान तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। तेलंगाना मॉडल भी एक किस्म का इनकम ट्रांसफर है जिसे आयोग को अपनाना चाहिए। गौरतलब है कि तेलंगाना में हर किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 8000 रुपए की फिक्स धनराषि मिलती है।

दूसरी बात, एमएसपी तय करने के तरीके में सुधार की जरूरत है। चूंकि किसान को जो एमएसपी मिलता वह खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य से सीधे जुड़ा हुआ है। मेरा सुझाव है कि एमएसपी का खाद्य पदार्थों से संबंध खत्म कर देना चाहिए। सरकार को गेहूं एमएसपी पर खरीदना चाहिए जिससे अंततः बाजार में खुदरा मूल्य निर्धारित होगा। पर यह सुनिष्चित करने के लिए कि किसानों को सी2 लागत पर 50 प्रतिषत मुनाफा मिले, एमएसपी पर इस मुनाफे को सीधे उनके जनधन बैंक अकाउंट में भेज देना चाहिए। उदाहरण के लिए, धान के मामले में सरकार को किसानों से इसे 1750 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदना चाहिए और शेष 590 रुपए प्रति क्विंटल को सीधे उनके अकाउंट में भेज देना चाहिए। इस तरह बिना खुदरा मूल्य प्रभावित हुए किसान को उनका वाजिब हक मिल जाएगा। कई दषकों पहले की गई गलती को सुधारने का यह एक मौका है। ❑❑

(लेखक प्रख्यात खाद्य एवं निवेश नीति विश्लेषक हैं, ये उनके निजी विचार हैं।)

ट्रेड वार का सार्थक पहलू

वर्तमान में अमरीका और चीन में चालू ट्रेड वार को लेकर मध्यधारा के अर्थशास्त्रियों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि यह वैश्विक मंदी को पलट सकता है। तर्क है कि अमरीका द्वारा स्टील, एलिम्युनियम तथा अन्य कच्चे माल पर आयात कर बढाये जाने से अमरीकी उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ेगी। उन्हें कच्चा माल महंगा खरीदना पड़ेगा। इससे अमरीकी उद्योग दबाव में आयेंगे। साथ साथ चीन और भारत जैसे देशों के माल का निर्यात् भी कम होगा। फलस्वरूप इनकी अर्थव्यवस्थायें डगमगायेंगी। अमरीकी कम्पनियों को कच्चा माल उपलब्ध नहीं होगा जिससे उनपर पुनः दबाव पड़ेगा। इस प्रकार अमरीका भारत और चीन सभी देशों के उद्याोग दबाव में आयेंगे। उनका आत्मविश्वास घटेगा और वे निवेश करना बंद कर देंगे। अमरीका विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था होने से वहां आने वाली मंदी का वैश्विक फैलाव हो जायेगा और विश्व अर्थव्यवस्था में मन्दी छा जायेगी।

मेरी समझ से इस विचार के विपरीत बिल्कुल अलग परिणाम हो सकते हैं। उपर के तर्कों का बिन्दुवार वैकल्पिक विश्लेषण मैं देना चाहूंगा। पहला बिन्दु है कि अमरीका द्वारा कच्चे माल पर आयात कर बढ़ाने से अमरीका के उद्योग दबाव में आयेंगे। लेकिन कच्चे माल के साथ साथ दूसरे उत्पादित माल पर भी अमरीका द्वारा आयात कर बढ़ाये जा रहे। मान लीजिय मैक्सिको और कैनेडा से आयात होने वाली कारों पर अमरीका ने आयात कर बढ़ा दिये। ऐसा करने से आयातित कारों का मूल्य अमरीका में बढ़ जायेगा। अमरीका में कारों का उत्पादन बढ़ेगा। मेरे एक जानकार ने बताया कि बीते समय में राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि लोहे के ढले हुये माल का आयात करने के स्थान पर इनका उत्पादन अमरीका में ही किया जाये। वे पहले चीन से ढले हुये माल का आयात करते थे। उनका धन्धा लगभग चौपट हो गया है क्योंकि ढला हुआ माल अब अमरीका में उत्पादित होने लगा है। इसलिये आयात कर बढ़ाने से कच्चे माल का दाम अवश्य बढ़ता है लेकिन साथ–साथ अमरीका

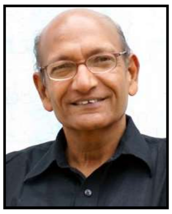

सच यह है कि वैश्विकरण को अपनाने से बड़ी कंपनियों को लाभ हुआ है और छोटे उद्योगों को हानि हुयी है। इसलिये अमरीका को संरक्षणवाद अपनाना पड़ा है। भारत सरकार को भी शीघ्रातिशीघ्र संरक्षणवाद को अपना कर अपने घरेलू व्यापारियों को खुला बाजार उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन देना चाहिये।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

में घरेलू उत्पादन भी बढ़ेगा जो कि अमरीका के लिये हितकारी होगा।

दूसरा बिन्दु है कि अमरीका द्वारा आयात कर बढ़ाने से भारत और चीन के निर्यात् प्रभावित होंगे साथ ही इनकी अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी का प्रवेश होगा। यह बात सही है कि भारत और चीन के निर्यात् प्रभावित होंगे। लेकिन भारत के निर्यात् कम और आयात ज्यादा हैं। अतः निर्यातों में जो गिरावट होगी उससे जादा आयातों में गिरावट आयेगी। जैसे अमरीका ने भारत से निर्यातित स्टील पर आयात कर बढ़ा दिये उससे भारत से अमरीका को निर्यात किये जाने वाले स्टील की मात्रा में गिरावट आयी। लेकिन साथ–साथ भारत यदि अमरीका से आयातित अखरोट और सेब के उपर आयात कर बढ़ा देता है तो इनका आयात कम हो जायेगा और भारत में इनका उत्पादन बढ़ेगा। अतः ट्रेड वार से उन देशों को लाभ होगा जो कि विदेश निर्यात् पर कम आश्रित हैं, और उनको नुकसान होगा जो निर्यात् पर जादा आश्रित हैं। जैसे भारत के निर्यात् कम और आयात ज्यादा हैं। अतः भारत के निर्यातों में जो कमी आयेगी उससे जो नुकसान होगा उसकी तुलना में भारत द्वारा आयातों में जो कमी आयेगी उससे लाभ ज्यादा होगा। अतः यह आशंका निर्मूल है कि विदेश व्यापार के कम होने से सभी देशों को नुकसान होगा।

तीसरा बिन्दु है कि सभी देशों में ट्रेड वार के कारण कच्चा माल महंगा हो जायेगा। सीधे देखा जाये तो यह बात सही है। लेकिन कच्चे माल के विकल्प उपलब्ध होते हैं। जैसे यदि अमरीका को भारत से निर्यातित एलिम्युनियम नही मिलेगा तो वहां एलिम्युनियम के दरवाजे बनाने के स्थान पर प्लास्टिक के दरवाजे बनाये जायेंगे। प्लास्टिक के दरवाजे बनाने में अमरीका में रोजगार ज्यादा उत्पन्न होंगे। इसलिये कच्चे माल का सीधा प्रभाव नकारात्मक पड़ने के बावजूद कुल प्रभाव नकारात्मक नहीं होगा।

चौथा बिन्दु है कि ट्रेड वार के कारण सभी देशों के उद्यमियों में आत्मविश्वास की गिरावट आयेगी। इस तर्क को सीधे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सच यह नहीं है। हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के सत्तारूढ़ होने के बाद आयात कर बढ़ाये गये लेकिन अमरीका की अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी है। अमरीकी उद्यमियों में अत्मविश्वास बढ़ा है, यह घटा नहीं है। कारण यह कि संरक्षणवाद को अपनाने से घरेलू उद्योगों को आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती है। उन्हें बाजार में अपना माल बेचने का अवसर मिलता है। उनके द्वारा उत्पादन बढ़ता है इसलिये ट्रेड वार के कारण देशों के उद्यमियों में आत्मविश्वास बढ़ने की मेरी दृष्टि में संभावना ज्यादा है।

भारत द्वारा अमरीका को निर्यात् कम और वहां से आयात ज्यादा किये जाते हैं। अतः संरक्षणवाद अपनाने से भारत को लाभ होगा। हमारे निर्यातों पर कम और आयातों पर जादा प्रभाव पड़ेगा। आयात कम होने से भारतीय उद्यमियों को मैदान मिलेगा।

अंतिम पांचवां बिन्दु है कि अमरीका की अर्थव्यवस्था में आयी मंदी का वैश्विक स्तर पर फैलाव हो सकता है। लेकिन जैसा ऊपर बताया गया है कि यही संदिग्ध है कि अमरीका में मंदी आयेगी। इसके अलावा यदि यह फैलाव होता भी है तो यह उन देशों को होगा जो अमरीका को किये गये निर्यातों पर भारी तरह से निर्भर हैं जैसे चीन द्वारा अमरीका को निर्यात ज्यादा और आयात कम किये जाते हैं। इसलिये अमरीका द्वारा संरक्षणवाद चीन के उपर प्रतिकूल प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तुलना में भारत द्वारा अमरीका को निर्यात् कम और वहां से आयात ज्यादा किये जाते हैं। अतः संरक्षणवाद अपनाने से भारत को लाभ होगा। हमारे निर्यातों पर कम और आयातों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आयात कम होने से भारतीय उद्यमियों को मैदान मिलेगा।

मेरा मानना है कि वर्तमान में ट्रेड वार अंत में सभी देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये भी लाभप्रद होगा। प्रश्न है कि फिर मुक्त व्यापार के लाभ को हम कैसे समझें? यहां दो पहलुओं को अलग अलग समझना होगा। यह सही है कि मुक्त व्यापार से सभी देशों को लाभ होता है। जैसे भारत द्वारा निर्यातित एलिम्यूनियम अमरीका को सस्ता उपलब्ध हो जायेगा और अमरीका द्वारा निर्यातित अखरोट भारत को सस्ता उपलब्ध हो जायेगा। लेकिन अंतर तब पड़ता है जब वैश्विक व्यापार का जुड़ाव बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हो जाता है। संरक्षणवाद अपनाने से बड़ी कम्पनियों को सीधे नुकसान होता है। उनका वैश्विक बाजार संकुचित होता है। तदानुसार छोटे व्यापारियों को लाभ होता है। इसलिये खुले व्यापार का सिद्धांत अपने में सही होते हुये भी जब खुले व्यापार का जुड़ाव बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियों से हो जाता हैं तब उसका अन्तिम प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। सच यह है कि वैश्विकरण को अपनाने से बड़ी कम्पनियों को लाभ हुआ है और छोटे उद्योगों को हानि हुयी है। इसलिये अमरीका को संरक्षणवाद अपनाना पड़ा है। भारत सरकार को भी शीघ्रातिशीघ्र संरक्षणवाद को अपना कर अपने घरेलू व्यापारियों को खुला बाजार उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन देना चाहिये। ❑❑

नोटबंदी - एक आर्थिक फैसला

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 की सांय 8 बजे 500 व 1000 रूपये की कागजी मुद्रा को चलन से हटा लेने का एक आर्थिक फैसला देष की अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाने के लिए किया गया था। परंतु 2019 के लोकसभा चुनाव आने की सुगबुगाहट शुरू होने से 2018 का नवंबर माह आते–आते देष के विपक्षी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री के इस नितांत आर्थिक फैसले को राजनैतिक रूप देने में लगे हुए है जिससे वे आम जनता से भारतीय जनता पार्टी और विषेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ताच्युत करने की घिनौनी राजनीति कर रहे है तथा प्रधानमंत्री के इस साहसिक फैसले नोटबंदी को राजनैतिक मुदद्ा बना रहे है।

30 अगस्त 2018 की सांय को विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी के द्वारा एक प्रेस वार्ता करके राफेल डील व नोटबंदी का घालमेल करते हुए कहा गया कि नोटबंदी एक बडा घोटाला है तथा कुछ मात्र 15–20 उद्योगपतियों को लाभ पंहुचाने के लिए ही यह फैसला हुआ। राहुल गांधी का निषाना नरेंद्र मोदी पर था तथा गांधी ने कहा कि 15–20 पूंजीपतियों को लाभ पंहुचाना ही नोटबंदी का एक मात्र उदेद्ष्य था। यह एक बडे घोटाले से कम नहीं है। नोटबंदी के दौरान किसानों, छोटे व मझोले व्यापारियों की जेब से पैसा निकालकर प्रधानमंत्री ने अपने नजदीकी 15–20 उद्योगपतियों की जेब में पैसा पंहुचा दिया। गुजरात में भाजपा के अध्यक्ष अमित षाह के को–ऑपरेटिव बैंक में 700 करोड रूपये जमा हुए थे। देष में चल रहे 500 व 1000 रूपये के सारे नोट वापस बैंकों में आ गये जो काला धन था उसे भी लोगों ने सफेद करा लिया और आम लोगों को बैंकों के आगे लाइनें लगवा कर कठिन हालातों से गुजरना पडा।

ज्ञातव्य हो कि 29 अगस्त 2018 को ही भारतीय रिजर्व बेंक के द्वारा जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि आठ नवंबर 2016 को घोषित नोटबंदी के तहत 15.31 लाख करोड रूपये मूल्य के 500 व 1000 रूपये के नोट बैंकों में वापस किए गये। नोटबंदी के दिन देष

2014 तक आयकर रिटर्न की संख्या 3.8 करोड थी जो 2017–18 में बढ़कर 6.86 करोड हो गई। नोटबंदी के कारण ही आयकर रिटर्न की संख्या में गत दो वर्ष में क्रमशः 19 प्रतिशत और 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

की मुद्रा व्यवस्था में 500 व 1000 रूपये के 15.40 लाख करोड रूपये मूल्य के रूपये चलन में थे। इस आधार पर लगभग 99.3 प्रतिषत प्रतिबंधित नोट वापस आ गये। आरबीआई की रिपेार्ट के अनुसार जाली नोटों के व्यापार पर भी इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पडा। नए नोट छापने में आरबीआई को 2016–17 में 7,965 करोड रूपये और जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान 4,912 करोड रूपये की राषि व्यय की गई। आरबीआई की इस वार्षिक रिपेार्ट के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मुदद् को हवा देने की एक राजनैतिक कोषिष की।

उधर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में वित्तीय मामलों के सचिव एससी गर्ग ने कहा कि काले धन पर रोक, आंतकी फंडिंग, डिजिटल ट्रांजैक्षन को प्रोत्साहन और नकली करेंसी को सिस्टम से बाहर निकालने जैसे उददे्षों को काफी हद तक हासिल कर लिया गया है तथा देष के किसी भी हिस्से में करेंसी की कोई परेषानी नहीं है। भारत सरकार में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि नोटबंदी का एकमात्र उददे्ष्य काले धन पर चोट कर अर्थव्यवस्था को संगठित करना था। नोटबंदी का व्यापक उददे्ष्य भारत को कर नियमों का पालन करने वाला समाज बनाना था, यह उददेष्य भी सफल रहा है।

विपक्ष का यह मानना है कि जब अधिकांष नोट वापस बैंकों में आ गये तो काला धन का खुलासा किस प्रकार हुआ तथा लोंगों ने अपना काला धन भी सफेद कर लिया तो फिर देष की जनता को परेषानी में क्यों डाला गया। वित्तमंत्री के अनुसार नोटबंदी के उपरांत 18 लाख ऐसे बैंक खाताधारकों की पहचान हो गई जिनके बैंक खाते में भारी भरकम राषि नोटबंदी के दौरान जमा की गई थी जिनसे बडी मात्रा में सरकार टैक्स वसूल कर रही है तथा पैनल्टी लगाई जा रही है। हालांकि वसूल की गई टैक्स व पैनल्टी की राषि का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। 2014 तक आयकर रिटर्न की संख्या 3.8 करोड थी जो 2017–18 में बढ़कर 6.86 करोड हो गई। नोटबंदी के कारण ही आयकर रिटर्न की संख्या में गत दो वर्ष में क्रमषः 19 प्रतिषत और 25 प्रतिषत वृद्धि हुई है। पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी गत दो वर्षों में लगभग 3 करोड बढ़ गई है। चालू वित्त वर्ष 2018–19 में भी प्रथम तिमाही में अग्रिम कर भुगतान के मामले में व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में 44. 1 प्रतिषत तथा कॉरपोरेट करदाताओं की संख्या में 17.4 प्रतिषत की वृद्धि हुई है। आयकर संग्रह 2013–14 में 6. 38 लाख करोड रूपये से बढ़कर 2017–18 में 10.02 लाख करोड रूपये हो गया है। नोटबंदी से पूर्व के दो वर्षों में आयकर संग्रह में 6.6 प्रतिषत और 9 प्रतिषत की वृद्धि हुई थी लेकिन नोटबंदी के बाद के दो वर्षों में इसमें 15 प्रतिषत और 18 प्रतिषत की वृद्धि हुई है तथा तीसरे साल भी यही रूझान देखने को मिल रहा है। नोटबंदी का सकारात्मक असर यह हुआ है कि इससे अर्थव्यवस्था अधिक संगठित हुई है। डिजिटल लेन देन की मात्रा भी बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकडे यह भी बताते है कि नोटबंदी के बाद नकदी के रूप में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत गत साल के उच्चतम स्तर पर पंहुच गई है। 2017–18 में सकल राष्ट्रीय सुलभ आय (जीएनडीआई) के मुकाबले घरेलू बचत 2.8 प्रतिषत हो गई है। नवंबर 2016 के बाद नकदी की किल्लत के कारण घरेलू बचत 2016–17 के दौरान 2 प्रतिषत कम हो गई थी। घरेलू वित्तीय बचत भी नोटबंदी के बाद 2016–17 में धीमी पड़ गई थी। जीएनडीआई के मुकाबले यह 6.7 प्रतिषत रह गई जबकि उससे पिछले वर्ष 2105–16 में यह 8.1 प्रतिषत थी। 2017–18 में यह बढ़कर 7.1 प्रतिषत हो गई। नोटबंदी के कारण ही डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है तथा इस क्षेत्र ने लंबी छलांग लगाई। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार भीम एप, यूपीआइ आधारित पेमेंट सिस्टम और आधारएनबेल्ड पेमेंट सिस्टम के कारण ही भारत में डिजिटल लेनदेन का आंकड़ा एक अरब के पार निकल गया है तथा इसके माध्यम से एक लाख करोड रूपये से अधिक की राषि का भुगतान हुआ तथा नोटबंदी के कारण ही अर्थव्यवस्था को संगठित करने में मदद मिली है। अतः नोटबंदी शुद्ध रूप में आर्थिक सुधार करने के लिए उठाया गया कदम था इसमें राजनीति करनी तथा इस फैसले को राजनीतिकजामा पहनाना देषवासियों के साथ अन्याय ही होगा।

नोटंबदी में 10,000 करोड रूपये वापस नहीं आये। आषा थी कि ढाई–तीन लाख करोड रूपये बैंकों में लौटने वाले नहीं है, परंतु बैंकिंग तंत्र ने काले धनधारकों से मिलीभगत कर ली, सरकार की इस कोषिष पर बैंक कर्मियों ने पानी फेरने की ही कोषिष की, जिसका अंदाजा सरकार नहीं लगा पायी। वापस नहीं आये 10,000 करोड रूपये के लगभग रकम नयी मुद्रा के छापने पर व्यय कर दी गई। आतंकी व नक्सलीवादी गुटों पर इसका प्रभावपूर्ण प्रभाव पड़ा। हालांकि कुछ समयोपरांत ही यह प्रभाव कमजोर पड गया। करदाताओं की संख्या में वृद्धि ही नोटबंदी के लाभदायक परिणाम की नतीजा कही जा सकती है। विपक्ष के अनुसार नोटबंदी का मूल उददे्ष्य कालेधन वालों की कमर तोड़ना था, जो टूट नहीं पायी और इसलिए विपक्षी दल इसको राजनैतिक मुददा बनाने का जतन कर रहे है। ❑❑

(लेखक सनातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुजफ्फरनगर के प्राचार्य व वाणिज्य संकाय में एसोसियेट प्रोफेसर पद से अवकाष प्राप्त है व स्वतंत्र टिप्पणीकार है।)

भारत का मिशन गगनयान

चांद पर जाने की तैयारी

इसरो की योजना के अनुसार 2022 तक भारत उन देशों में शामिल हो जायेगा जो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की क्षमता रखते हैं। रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देश होगा जिसे यह क्षमता प्राप्त हो जायेगी।

– निरंकार सिंह

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से कहा था कि 2022 के पहले भारत का कोई बेटा या बेटी अंतरिक्ष में स्वदेशी गगनयान से पहुंचेगा। इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले इस मानवरहित अंतरिक्ष अभियान का नाम 'गगनयान' है। 'गगनयान' सिर्फ इसरो का ही अभियान नहीं होगा बल्कि देष के कई संस्थानों और दिव्यांगों के योगदान से बना राष्ट्रीय मिषन होगा। इसरो की योजना के अनुसार 2022 तक भारत उन देषों में शामिल हो जायेगा जो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की क्षमता रखते हैं। रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देष होगा जिसे यह क्षमता प्राप्त हो जायेगी। इसरो यदि इसमें कामयाब होता है तो दुनिया भर में उसका डंका बजेगा। 'गगनयान जीएसएलवी मार्क–3 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जायेगा। यह हमारा सबसे भारी–भरकम और सफल रॉकेट है। 2014 में ही इसरो क्रू मॉडयूल टेस्ट कर चुका है। क्रू मॉडयूल वही ढांचा होता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं और सुरक्षित धरती पर लौटते हैं। 'स्पेस सूट' तो हम तैयार कर ही चुके हैं। साफ है कि अब एक प्रोजेक्ट के तौर पर इस मिषन को आगे बढ़ाने की देर है। इसरो ने अब तक जो भी वादे किये हैं, वे पूरे हुए हैं। इसलिए गगनयान मिषन की सफलता की उम्मीद बंधती है।

प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पिछले 15 सालों से एक परियोजना पर काम कर रहे इसरो को आखिरकार एक निष्चित समय सीमा मिल गई है। वैसे तो मानव अंतरिक्ष मिषन को इसरो की प्लानिंग कमेटी द्वारा 2004 में ही मंजूरी मिल गई थी तभी से इसकी तैयारी चल रही है। हालांकि, शुरूआत में इस मिषन को वर्ष 2015 में लॉन्च किये जाने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु वास्तव में मिषन को लॉन्च करने के बारे में स्पष्टता की कमी थी। एक मानव मिषन के लिए इसरो को प्रमुख रूप से विषिष्ट क्षमताओं को विकसित करना होगा

चंद्रयान-2 दुनिया का पहला मिशन होगा, जो चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक पहुंचेगा। इसरो के अनुसार मार्च 2019 से पहले 19 मिशन लांच किये जायेंगे।

जिनमें अंतरिक्ष यान को उड़ान के बाद पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता और एक ऐसे अंतरिक्ष यान का निर्माण जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी स्थितियों में रह सकें आदि शामिल है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आवष्यकताओं में से एक लॉन्च वाहन का विकास करना है जो अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जाने में सक्षम हो।

हाल ही में 6 जून 18 को मोदी सरकार ने 4,338.2 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर जीएसएलवी मार्क–3 की अगली 10 उड़ानों के लिए वित्तपोषण को मंजूरी दी है, इससे भारी पेलोड भेजने के लिए क्रायोजेनिक तकनीक को पूरा करने में इसरो को मदद मिलेगी। इस पहल का मुख्य उद्देष्य वर्ष 2024 तक जीएसएलवी मार्क–3 मिषन को प्रोत्साहित करना था। हालांकि इसरो ने मानव क्रू मॉड्यूल, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन सहायता प्रणाली जैसी तकनीक विकसित कर ली है, किन्तु वर्ष 2022 तक वास्तविक उड़ान से पूर्व दो मानव रहित मिषन और अंतरिक्ष यान को जिओसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क–3 का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जायेगा। इसरो के पूर्व चेयरमैन के. राधाकृश्णन जिनके नेतृत्व में मंगलयान मिषन वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था, ने 'गगनयान' मिषन को इसरो के लिए 'टर्निंग पॉइंट कहकर सम्बोधित किया है। इसी सिलसिले में इसरो ने चंद्रयान–2 की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है।

इसरो के चेयरमैन के सिवन के अनुसार इसे 3 जनवरी को लॉन्च किया जायेगा। यह 16 फरवरी को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक तय स्थान पर उतर जायेगा। इसके अलावा भारत 2022 में अंतरिक्ष में मानव मिषन गगनयान भी भेजेगा। चन्द्रयान–2 का वजन 600 किलोग्राम बढ़ाया गया है। दरअसल, प्रयोगों के दौरान पता चला कि उपग्रह से जब चन्द्रमा पर उतरने वाला हिस्सा बाहर आयेगा तो यह हिलने लगेगा। लिहाजा, इसका भार बढ़ाने का फैसला किया गया। अब यह उपग्रह समेत 38 क्विंटल से कुछ ज्यादा होगा। इसरो की मार्च 2019 से पहले तक 19 मिषन लॉन्च करने की योजना है। भार बढ़ने की वजह से अब इसे जीएसएलवी से लॉन्च नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए जीएसएलवी मैक–3 में बदलाव किया गया है। यह जीएसएलवी–मैक–3 एम1 कहलायेगा। चन्द्रयान–2 पहले इसी साल अक्टूबर में लॉन्च करने की योजना थी। यह दुनिया का पहला मिषन होगा, जो चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक पहुंचेगा। इसरो के अनुसार मार्च 2019 से पहले 19 मिषन लांच किये जायेंगे।

इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिषन गगनयान का खाका भी तैयार कर लिया है। इसके जरिए तीन अंतरिक्ष यात्री 350 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगायेंगे। वे बेहद कम गुरूत्वाकर्षण से जुड़े प्रयोग करेंगे। यह मिषन दिसम्बर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे पहले यह प्रयोग दो बार मानवरहित किया जायेगा। गगनयान से भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को करीब तीन साल प्रषिक्षण दिया जायेगा। इसे ध्यान में रखते हुए इनका चयन भी जल्द होगा। इसमें एयरफोर्स के पायलटों को प्राथमिकता दी जायेगी। अंतरिक्ष में पांच–सात दिन रहने के बाद अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटेंगे। यान को तय कक्षा में पहुंचने में 16 मिनट और धरती पर वापस आने में 36 मिनट लगेगें। गगनयान पर करीब 10 हजार करोड़ रूपये का खर्च आयेगा। यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानव मिषन की तुलना में काफी कम होगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन पहले ही चांद पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब चांद तक पहुंचने की रेस में दो एषियाई देष भारत और इजरायल है। ऐसे में यह देखना होगा कि भारत और इजरायल में से कौन सा देष चांद पर पहुंचने वाला चौथा देष बनेगा। इस मिषन के तहत भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पहली बार अपने यान को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोषिष करेगा। भारत के चन्द्रयान–1 ने ही पहली बार चांद पर पानी की खोज की थी।

चन्द्रयान–2 इसी अभियान का विस्तार है। यह भारत की दूसरी चांद यात्रा है। इसरो के 800 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट चन्द्रयान–2 मिषन का हिस्सा ही है। चन्द्रयान–2 मिषन के जरिए भारत दक्षिण ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैडिंग कर, छह पहियों वाले रोवर को स्थापित

करने की तैयारी में है, ताकि चांद की सतह से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सकें। अपने इस मूल मिषन के लिए भारत अपने सबसे भारी रॉकेट बाहुबली का इस्तेमाल कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चन्द्रयान–2 के चन्द्रमा की कक्षा तक पहुंचने के बाद, लैंडर आर्बिटर से अलग हो जायेगा और चन्द्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। लैंडर के अन्दर लगे 6 पहिये वाले रोवर अलग हो जायेंगे और चन्द्रमा की सतह पर आगे बढ़ेंगे। रोवर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह चन्द्रमा की सतह पर 14 दिन तक रह पायेगा और 150–200 किमी तक चलने में सक्षम होगा। इसरो के चेयरमैन के अनुसार रोवर फिर 15 मिनट के भीतर चन्द्रमा की सतह के आंकड़े और छवियों को पृथ्वी पर भेज देगा। 14 दिनों के बाद रोवर स्लीप मोड में आ जायेगा। यह चांद के खनिज, तत्वों की संरचना, चांद के वातावरण और वाटर आइस का भी अध्ययन करेगा। इसरो ने अपना पहला चन्द्र अभियान चन्द्रयान–1 वर्ष 2008 में लान्च किया था।

इस बार भी अंतरिक्ष यात्री का चुनाव वही संस्था करेगी जिसने 1984 में अंतरिक्ष अभियान के लिए राकेष शर्मा का चुनाव किया था। भारतीय वायु सेना के अन्तर्गत आने वाला संस्थान (आईएएम) इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव करता है। आईएएम कमांडेट एयर कमोडोर अनुपम अग्रवाल ने कहा कि इसके अलावा भी उन्होंने चार विषेष क्षेत्रों में मदद मांगी है। जिसमें बुनियादी और अग्रिम प्रषिक्षण, हैबिटाट, मॉडयूल, क्रू कैप्सूल की मानव इंजीनियरिंग और फ्लाईट सर्जन सपोर्ट शामिल है। अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव एक जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 14 से 12 महीनों का समय लगता है। मूलभूत मूल्यांकन में मनोवैज्ञानिक एवं मेडिकल टेस्ट सम्मिलित होते है। कमांडेंट अग्रवाल के अनुसार गगनयान अभियान के लिए 30 प्रतिभागियों के समूह की जरूरत होती जिसमें से 15 का चुनाव करके उन्हें मूलभूत प्रषिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष यात्रियों को जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और दवाईयों के बारें में भी प्रषिक्षण दिया जायेगा। आईएएम जहां उन्हें मेडिसिन का प्रषिक्षण देगा वहीं दूसरे क्षेत्र के विषेषज्ञ भी प्रषिक्षण देंगे। अंतरिक्ष फ्लाइट का एक जटिल प्रारूप होता है फ्लाइट सर्जन सपोर्ट। इसे आईएएम द्वारा मुहैया कराया जायेगा। इस समय आईएएम विषिष्ट सिमुलेटर जैसे अग्रिम प्रषिक्षण नहीं दिया जा सकता। इसे अभी विकसित भी नहीं किया जा सकता और इसी पैराबोलिक फ्लाइट प्रषिक्षण के लिए भारत को दूसरे देष के मदद की आवष्यकता पड़ सकती है। ❑❑

(लेखक हिन्दी विश्वकोश के सहायक संपादक रह चुके हैं। आज कल स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं।)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

जनता से जुड़े मुद्दे उठाना कब शुरू करेंगे राजनीतिक दल?

आगामी विधानसभा चुनाव नौकरी, वेतन, मुद्रास्फीति, विकास और वास्तविक विकास दर जैसे गंभीर मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है. कीमतें बढ़ रही हैं, रुपया दिनोंदिन गिरता जा रहा है। खेती की लागत दर मुद्रास्फीति की चुनौती का मुकाबला नहीं कर पा रही है। नकदी का अभी भी अभाव है। व्यापार जगत में भी एक ठहराव है। लेकिन, यह भी सच है कि इन तथ्यों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। कर–राजस्व की वसूली में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये सभी तथ्य मिलकर एक मिलाजुला परिदृष्य प्रस्तुत करते हैं। क्या विकास का अर्थ जनसाधारण के कुषल–क्षेम से लगाया जाना चाहिए? बताया जा रहा है कि जनता 431 सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठा रही है।

विपक्षी पार्टियां कीमतों, राफेल खरीद में कथित भ्रष्टाचार और मध्यप्रदेष के व्यापम मामले को लेकर तो हंगामा मचा रही हैं। लेकिन, इसे लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि अकर्मण्य पुलिस बल के द्वारा तीन लाख लोगों की भर्ती क्यों की गई?

जनता सभी राजनीतिक दलों को गौर से देख रही है। इनमें से कुछ ही ने संभवतः जनता से जुड़े मुद्दों को छूने की कोषिष की हो।

ज्यादातर दलों के लिए नरम या गरम हिन्दुत्व ही मुख्य मुद्दा बनता दिख रहा है। क्या ऐसा इसलिए है, क्योंकि राजनीति के अखाड़े के खिलाड़ियों को गंभीर मुद्दों की समझ ही नहीं है? बीजेपी के 'राम' और कांग्रेस की 'रामपथ गमन यात्रा' एक–दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। दरअसल, धर्मनिरपेक्ष तुष्टिकरण के असफल होने के संकेत के बीच कई दषकों के बाद गैर–मुस्लिम वोटों को साधने की कोषिष की जा रही है।

ज्यादातर दलों के लिए नरम या गरम हिन्दुत्व ही मुख्य मुद्दा बनता दिख रहा है। क्या ऐसा इसलिए है, क्योंकि राजनीति के अखाड़े के खिलाड़ियों को गंभीर मुद्दों की समझ ही नहीं है? बीजेपी के 'राम' और कांग्रेस की 'रामपथ गमन यात्रा' एक–दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। दरअसल, धर्मनिरपेक्ष तुष्टिकरण के असफल होने के संकेत के बीच कई दशकों के बाद गैर–मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है।

– **शिवाजी सरकार**

महंगाई पर हल्का शोर मचाने के अलावा विपक्ष गंभीर मुद्दों को उठाने में नाकामयाब दिख रहा है। थोक मूल्य सूचकांक एक संकेतक है। साल 2010 से अब तक कीमतों में 65 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। राजनीतिक पार्टियां महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही हैं। दरअसल, वे बढ़ती कीमतों को कोई समस्या भी नहीं मानते।

सियासी दल इस तरह का षिगूफा छोड़ रहे हैं कि महंगाई पर काबू पाया ही नहीं जा सकता है। दरअसल, महंगाई पर राजनीतिक दलों के इस रवैये से भारतीय अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है। इससे कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही वेतन–भत्तों आदि में भी वृद्धि हो रही है। नौकरी की कमी के साथ ही इसने व्यापार और सरकारी खर्चे की पूरी प्रणाली को असंतुलित कर दिया है। यह स्थिति जनता के लिए एक अनकही त्रासदी का कारण बन रही है और इससे वास्तविक गरीबी बढ़ी है।

कीमतों में वृद्धि की मुख्य वजह सरकारी नीतियों– शुल्क, रेल और बसों के बढ़ते किराये और नगर निगम के टैक्स में होने वाली बढ़ोतरी– के साथ उत्पादों पर बार–बार लगने वाला जीएसटी टैक्स है। जीएसटी की वजह से हाउस टैक्स के साथ ही दूसरी कई सेवाओं पर लगने वाले टैक्स दुगुना हो गए हैं। इसने खाने–पीने की चीजों को भी महंगा कर दिया है, जबकि किसानों की समस्या जस–की–तस बनी हुई है। क्या सड़क टोल पर जीएसटी लगनी चाहिए?

सड़क निर्माण महज चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की इकाई बनकर रह गया है। पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स के जरिए 1.13 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली के बावजूद किसी सियासी दल ने टोल के औचित्य पर सवाल नहीं उठाया। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि जब एक किलोमीटर सड़क बनाने में 5 करोड़ रुपये का खर्च आता है, तो आठ किलोमीटर सड़क बनाने में 845 करोड़ रुपये कैसे लग गए।

महंगाई पर हल्का शोर मचाने के अलावा विपक्ष गंभीर मुद्दों को उठाने में नाकामयाब दिख रहा है। थोक मूल्य सूचकांक एक संकेतक है। साल 2010 से अब तक कीमतों में 65 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त कुछ सियासी दलों ने सड़क टोल को कम करने का वादा किया था। हर साल टोल का बढ़ते जाना अनुचित है। पूरी दुनिया में इस तरह के टोल में धीरे–धीरे कमी की जाती है। होना तो यह चाहिए कि लागत वसूल कर लिए जाने के बाद या तो कम से कम वसूली होनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली–नोएडा–डायरेक्ट टोल ब्रिज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था।

ज्यादातर उत्पादों पर तर्कहीन तरीके से टैक्स लगाए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि लोगों को तीन साल तक बीमा प्रीमियम क्यों भरना चाहिए, जबकि कंपनियां इसके एवज में ब्याज का एक पैसा भी नहीं देती हैं। रजिस्ट्रेषन शुल्क 8 प्रतिषत या उससे ज्यादा क्यों होना चाहिए? जनता पर पार्किंग शुल्क क्यों लगाया जाना चाहिए, जबकि सभी पार्किंग शुल्क पहले से ही ज्यादा है? यह इस बात को दर्षाता है कि भारतीय नौकरषाही या देष के नेता इस बात से अनजान हैं कि वे बाजार को कैसे तबाह कर रहे हैं।

पेट्रोल की कीमतों में भी दैनिक वृद्धि अनावष्यक है। किसी दल ने भी कीमतें तय किए जाने की इस प्रणाली पर सवाल खड़ा नहीं किया है। इसके अलावा, किसी ने यह नहीं कहा है यह नीति तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली है, जो भारतीय समुद्री तटों से 40 डॉलर प्रति बैरल से भी कम दर पर तेल निकाल रही हैं और इसे 80 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से बेच रही हैं। जाहिर है, कीमतों को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छाषक्ति का अभाव है।

दरअसल, राजनीतिक दल ग्रामीण इलाकों की जमीनी वास्तविकता से अनजान हैं। आलू और गेहूं के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि सरकार ने कई दूसरे

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। नकदी की कमी और टैक्सकर्मियों के द्वारा छापेमारियों ने ग्रामीण बाजार को जटिल बना दिया है। भुगतान, जो पहले लगभग तत्काल हो जाया करते थे, अब देरी से हो रहे हैं। इस स्थिति ने व्यापार के विकास दर को धीमा कर दिया है।

रेल टिकटों को रद्द कराने पर भारतीय रेलवे द्वारा किराया वापस न किए जाने जैसे धन के गोलमाल पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। किसी भी राजनीतिक दल ने इस गलत परंपरा की जांच की मांग नहीं की। आष्चर्य की बात तो यह भी है कि इस तरह के करोड़ों रुपये की अनैतिक कमाई के बावजूद रेलवे वित्तीय रूप से बीमार क्यों है? सार्वजनिक क्षेत्र की सड़क निर्माण इकाइयां भी गलत तरीके से शुल्कों को बढ़ाती रही हैं। क्या किसी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है? रेल और सड़क से यात्रा करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे हालात आम लोगों के बजट को बिगाड़ कर रख देती हैं। इस स्थिति ने विद्यार्थियों के जीवन को मुष्किल बनाया है।

प्राथमिक षिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की षिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। मौखिक सहानुभूति के अलावा कोई भी सियासी दल यह सवाल नहीं करता कि आखिर निजी विश्वविद्यालयों के ट्यूषन और दूसरे शुल्क इतने ज्यादा क्यों हैं? महंगी षिक्षा ने विद्यार्थी समाज को भारी कर्ज के नीचे दबा दिया है। दूसरी ओर, षिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, क्योंकि निजी विश्वविद्यालय यूजीसी या एआईसीटीई के निर्धारित मानदंडों के मुताबिक वेतन नहीं देते हैं।

दरअसल, ज्ञान और षिक्षा के क्षेत्र में कौषल और प्रतिभा के विकास के लिए जरूरी राजनीतिक समझ की कमी है, जबकि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में षिक्षा को लेकर चिंता देखी जा सकती है। सिर्फ संस्थाओं की संख्या को लेकर शेखी बघारने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष ऐसी हजारों संस्थाएं घाटे की वजह से बंद भी हो जाती हैं।

व्यापारिक संस्थाएं इस विषम आर्थिक हालात और कामकाज में बड़ी पूंजी लगने के मुद्दे पर हल्की चर्चा तो करती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो इस पर बिल्कुल मौन हैं।

आष्चर्यजनक तौर से बैंकों को महज कुछ सौ लोगों ने लूटा है, जबकि शेष 99.99 प्रतिषत लोग इससे परेषान हैं। एनपीए की बड़ी मात्रा ने जमा ब्याज दर को प्रभावित किया है। एनपीए की वजह से ही बैंकों में पैसा जमा करना अब ग्राहकों के लिए आकर्षक नहीं रह गया है, क्योंकि इन पैसों पर बहुत कम ब्याज दिया जाता है। एक नुकसानदेह प्रणाली के तहत इस पैसे पर टीडीएस काट कर गोलमाल किया जा रहा है।

सिर्फ न्यूनतम राषि रखने वाले ग्राहकों के खातों से ही 'घाटे' में चल रहे पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने 11,000 करोड़ रुपये की कमाई की है। कथित तौर पर 'डेड' कहे जाने वाले बैंकों के खातों में ही करोड़ों रुपये जमा हैं। इन खातों को चालू करने की इजाजत भी नहीं दी जाती है।

क्या किसी राजनीतिक दल ने ब्याज पर टैक्स लगाने की नीति के औचित्य को कठघरे में खड़ा किया है, इस गलत टैक्स नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में वरिष्ठ नागरिक और कम कमाई करने वाले दूसरे गरीब लोग शामिल हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, देष के कर–राजस्व, खासकर आयकर में 16 प्रतिषत की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में जारी सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक रिफंड और वास्तविक जमा 6.6 प्रतिषत से ज्यादा नहीं है। इन सबके बावजूद, राजनीतिक दलों ने न तो आयकर को कम करने की मांग की और न ही जोरषोर से 'टैक्स टेरर' के मामले को उठाया। ये समस्याएं देष के आर्थिक हालात को बीमारू बनाने पर तुली हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि समस्या का इलाज करने वाला डॉक्टर पूरे परिदृष्य से गायब है। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

गंगा-पुत्र स्वामी सानंद का आत्मोत्सर्ग

सनातन धर्म में गाय, गंगा और गायत्री को अप्रतिम स्थान प्राप्त है, तथा उन्हें मां के रूप में संबोधित किया जाता है। गाय, गंगा और गायत्री के बिना सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। हजारों वर्ष से परतंत्रता की बेड़ियों ने भारत मां को जकड़ रखा था, फलस्वरूप भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म पर चारों ओर से प्रहार हो रहे थे और उसे नष्ट करने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय अस्मिता एवं संस्कृति की सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर नवजागरण अवश्य दिखाई पड़ रहा था किंतु स्वतंत्रता प्राप्त होते ही वह लुप्त प्राय हो गया, फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में गौरक्षा के नाम पर देश के साधु संत समाज को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा, जिसमें उसे स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार नेहरू की गोलियों की बौछार झेलनी पड़ी और अनेकानेक साधु संत काल के गाल में समा गए।

स्वामी करपात्री जी उक्त घटना से कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। कहा तो यह जाता है उस घटना से आक्रोशित होकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर्वनाश हो जाने का श्राप दिया था। स्वामी करपात्री जी के गोलोक प्रस्थान के पश्चात गौरक्षा आंदोलन पूर्णरूपेण समाप्त हो गया और आज गाय गौशाला से बाहर सड़क पर आकर स्वयं के अस्तित्व की रक्षा के लिये संघर्ष कर रही है। गायत्री तो पंडित श्री राम शर्मा के गायत्री परिवार में ही सीमित होकर रह गई है। शायद ही गायत्री परिवार से बाहर कोई अन्य परिवार सनातन धर्मी होने के बावजूद गायत्री आराधना करता हो। मां गंगा का तो कहना ही क्या है विकास के नाम पर उन्हें जगह–जगह स्थान स्थान पर बांध दिया गया है, गंगाजल का अविरल प्रवाह बाधित है, गोमुख से निकलने वाला गंगाजल सरकारी विकास यात्रा में खो जाता है, गंगासागर तक उस जल की एक बूंद भी नहीं पहुंच पा रही है। गंगा की यह दुर्दशा 1 दिन में ना होकर लंबे समय से की गयी निरंतर अवहेलना का परिणाम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसके जल को विकास के नाम पर प्रवाहित होने से रोककर अनेक नहरे बनाते हुए विद्युत उत्पादन का अजस्र स्रोत बना दिया गया है। फलस्वरूप मां गंगा में पानी का पूर्ण अभाव हो गया है तथा गंगाजल के स्थान पर शहरों के मल जल एवं उद्योगों

गंगा है तो देश है, गंगा है तो संस्कृति है, सभ्यता है। गंगा नहीं तो न देश रहेगा और न ही उसकी संस्कृति और न सभ्यता।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

के द्वारा छोड़े गए गंदे पानी का गंदा नाला बन कर रह गई है।

आज मां गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए तथा उसके अविरल प्रवाह को बनाए रखने के नाम पर करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जा रहे हैं, किंतु खर्च की जा रही वह धनराशि गंगा सफाई में रंच मात्र भी योगदान न देकर केवल धन्ना सेठों की तिजोरियो की राशि में ही अभिवृद्धि कर रही है। गंगा स्वच्छता अभियान की निरर्थकता एवं उस पर और उसके नाम पर हो रहे निरर्थक व्यय को देखते हुए प्रो जी.डी. अग्रवाल ने गंगा के अविरल प्रवाह को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया और वह प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल से स्वामी सानंद बन गए। स्वामी सानंद ने गंगा के अविरल प्रवाह को बनाए रखना अपने जीवन का एक मात्र उद्देश्य बना लिया, जिसके लिए वह अकेले चलते हुए संघर्ष करते रहे तथा मां गंगा की रक्षा के लिए अपने आंदोलन को धार देते रहे। केंद्र में सरकार बनने के बाद गंगा के लिए अलग मंत्रालय बनाकर भारी भरकम बजट आवंटित करने से सबको लगा था कि अब तो गंगा की सफाई होकर ही रहेगी, किंतु निकले वहीं ढाक के तीन पात। गंगा सफाई के नाम पर अनेकानेक परियोजनाओं को संचालित करने हेतु धन का अत्यधिक व्यय कर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया कि गंगा की सफाई का कार्य किया जा रहा है, किंतु योजनाएं तो अनेक बनी किंतु धरातल पर गंगा की सफाई के नाम पर कोई कार्य नहीं हो सका। गंगा मृतप्राय स्तिथि में थी और अब अपनी मृत्यु के और नजदीक पहुंच गई है, जिसे देखते हुए स्वामी सानंद ने अपने अंतिम संघर्ष के लिए दृढ़ निश्चय होकर 22 जून को आमरण अनशन की घोषणा कर दी। सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रयास न किए जाने से दृढ़ निश्चयी श्री स्वामी सानंद आमरण अनशन पर बैठ गए तथा 112 दिन के आमरण अनशन के पश्चात गोलोक वासी हो गए। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कोई सार्थक प्रयास उनके अनशन को समाप्त करने के लिए नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती अनशन स्थल पर तो अवश्य आई किंतु कोई सार्थक प्रयास कर स्वामी सानंद के अनशन को समाप्त नहीं करा सकी, वापस जाकर नितिन गडकरी से स्वामी सानंद की दूरभाष पर वार्ता कराई गई, किंतु उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। गडकरी स्वामी सानंद से अनशन समाप्त करने का अनुरोध करते रहे और स्वामी सानंद गंगा की अविरल धारा अपने जीवन के मूल्य पर मांगते रहे, किंतु केंद्रीय मंत्री गडकरी उन्हें वह नहीं दे सके। श्री गडकरी का यह प्रयास था कि किसी रूप में स्वामी सानंद अनशन समाप्त कर दें जिसके जवाब में स्वामी सानंद ने उनसे कहा अब मैं आप लोगों के झांसे में नहीं आने वाला। मेरा जीवन गंगा के लिए समर्पित है। कांग्रेस की सरकार के समय भी उन्होंने अनशन किया था और तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश उनके पास अनशन स्थल पर आए थे और स्वामी सानंद की मांगों को मानते हुए अनेक परियोजनाओं को तत्कालीन सरकार ने रोक दिया था, जिससे उत्तराखंड का सामान्य जनमानस स्वामी सानंद के आंदोलन को विकास के प्रतिकूल मानते हुए उनके विरोध में भी खड़ा हुआ था, किंतु उनके द्वारा अपने आंदोलन के औचित्य तथा उत्तराखंड की सुरक्षा हेतु मां गंगा के अविरल प्रवाह के महत्व का प्रतिपादन कर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरुप जनसामान्य तो उनके साथ जुड़ा किंतु सरकार के कान तक

स्वामी सानंद को स्वदेशी जागरण मंच ने दी श्रद्धांजलि

गंगापुत्र स्वामी सानंद जी स्मृति में देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने स्वामी जी के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि आज जीडीपी आधारित विकास के सोंच की जो गंगा बहायी जा रही है, इसी सोंच में गंगा के अविरल प्रवाह को बाधित किया है। एक तरह से विकास के नाम पर यह विनाश की तस्वीर पेश करती है। महाजन ने कहा कि झटपट जीडीपी बढ़ाने के लिए अपनाये जा रहे दोनों रास्ते पूंजीवदी और समाजवादी अब अप्रासंगिक हो चुके है। ऐसे में जरूरत है कि हम राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा सुझाए तीसरे विकल्प पर चलकर राष्ट्र की उन्नति का प्रयास करें। ठेंगड़ी जी के रास्ते विकास की मंजिल भी हासिल होगी और गंगा जैसी हजारों नदियों का जीवन भी सुरक्षित, संरक्षित होगा।

डॉ. महाजन ने बताया कि स्वामी सानंद जी के बलिदान से देश में एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है कि स्वामी जी ने गंगा के लिए शहादत दी है, इसे बदलने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर हो रहे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकना चाहिए तथा तीसरे विकल्प को अपनाकर श्रेष्ठ समाज और देश का निर्माण करना चाहिए।

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी और स्वामी सानंद जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर प्रांत संयोजक श्री सुरेंद्र सिंह, महानगर संयोजक डा. सुधांशु ध्यानी, सहप्रांत संयोजक श्री धर्मेंद्र चौहान, बीएमएस के गोविंद सिंह विष्ट, श्री रामाकांत आदि उपस्थित रहें। ❑

न तो उनके विचार और न ही उनके आंदोलन आमरण अनशन की गूंज ही पहुंच सकी। सरकार उनकी ओर से पूर्णरूपेण अन्यमनस्क बनी रही और उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करती रही, अंततोगत्वा वही हुआ जिसकी आशंका थी, स्वामी सानंद ने असामान्य परिस्थिति में अपनी अंतिम सांसे ली तथा गो–लोकवासी हो गए।

स्वामी सानंद प्रोफ़ेसर होने के साथ–साथ एक पर्यावरणविद भी थे, उन्हें सरकार द्वारा ही समय–समय पर पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए थे, जिनका निर्वहन उन्होंने अत्यंत कुशलता के साथ किया था। वह आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग और पर्यावरण विभाग में प्राध्यापक रह चुके थे तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रथम सचिव, और राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के सलाहकार सरकार द्वारा बनाए गए थे। साध ही वह महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के मानद प्रोफ़ेसर थे। उनके पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्य अविस्मरणीय है। गंगा के प्रति उनकी निष्ठा अप्रतिम थी जिसके मूल में गंगा के साथ साथ मानव सभ्यता को बचाने की भावना निहित थी, जिसके लिए वह निरंतर प्रयासरत थे, संघर्षरत थे। यह उनका गंगा के संरक्षण के लिए चौथा अनशन था। तीन बार तो किसी न किसी रूप में बचा लिया गया, एक बार तो जयराम रमेश ने उनकी मांगे स्वीकार कर तथा उसके पश्चात दो बार गोविंदाचार्य के प्रयास से उनका अनशन समाप्त करा कर प्राण बचाए गए थे, किंतु इस बार कोई जयराम रमेश या गोविंदाचार्य सामने नहीं आया और सरकार की निष्क्रियता से उन्हें मौत का साक्षात्कार करना पड़ा।

स्वामी सानंद सच्चे अर्थों में गंगा पुत्र थे उन्होंने अपने जीवन के मूल्य पर गंगा की अविरल धारा प्रवाहित करने के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। उनका मानना था कि गंगा पर बन रहे बांध तथा जल विद्युत परियोजनाएं सभ्यता के विकास में सहयोग न कर गंगा को समाप्त करने के साथ–साथ समस्त पारिस्थितिकी को भी समाप्त करने के लिए उद्यत है। इनसे न केवल गंगा की अविरल धारा बाधित होती है, अपितु इसके साथ ही आसपास बसे हुए मानवों के साथ ही अन्य जीव जंतुओं को भी विस्थापित करती है, तथा वनों को तबाह कर समाप्त करती है। अब तक विभिन्न नदियों पर बनाए गए बांधों के प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। इनसे जहां एक और नदियों का अस्तित्व समाप्त प्राय हो गया है वहीं दूसरी ओर नदियों के तट पर निवास करने वाले मानव समूह को भी वहां से पलायन करना पड़ा है। स्वामी सानंद का यह मानना था की गंगा के साथ साथ ही हिमालय पर्वत पर भी मानवीय हस्तक्षेप विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रित कर रहा है। पर्वतों को काट–छांटकर बनाई गई सड़कें वहां की पारिस्थितिकी को दुष्प्रभावित करती हैं। फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र के साथ ही साथ गंगा का मैदानी भाग भी उसके दुष्प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा किंतु दुर्भाग्य है कि उनकी बात की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

स्वामी सानंद ने गंगा की समस्या समाधान के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में अनेक पत्र भी भेजकर अनुरोध किया था कि गंगा की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरणविदों की ओर से अधिनियम के प्रस्तावित ड्राफ्ट 2012 पर शीघ्रातिशीघ्र संसद में कानून बनाने अथवा अध्यादेश लाने की कार्यवाही की जाए, उत्तराखंड की भागीरथी अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर व धौलीगंगा नदियों पर निर्माणाधीन व प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाई जाए। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में वन कटान, खनन और किसी भी प्रकार के खुदान पर पूर्ण रोक लगायी जाय। गंगा से जुड़े फैसलों के लिए गंगा भक्त परिषद का गठन किया जाए, परिषद में गंगा में आस्था रखने वाले लोगों के साथ ही विशेषज्ञ शामिल हो। इस परिषद में केंद्र और राज्य सरकार या ब्यूरोक्रेट्स का हस्तक्षेप ना हो। एक ऐसा कानून बने जिससे जीने का अधिकार और समुदाय के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में सर्वोत्तम उपयोग कराया जा सके।

उल्लेखनीय है स्वामी सानन्द की ही तरह मातृ सदन के ही स्वामी निगमानंद की मृत्यु वर्ष 2011 में मां गंगा की सुरक्षा तथा उसके आंचल से खनन माफिया को दूर रखने की मांग को लेकर प्रारंभ किए गए अनशन के दौरान ही हुई थी। इसी प्रकार स्वामी गोकुलानंद की मृत्यु 2012 में मां के आंचल को खनन माफिया से बचाने के संघर्ष में ही हुई थी, किंतु इन महा तपस्वियो के संघर्ष एवं आत्मोत्सर्ग का परिणाम भी निकल कर सामने नहीं आया और ना ही समाज के समक्ष किसी प्रकार का प्रश्नचिन्ह ही खडा हुआ, लगता है कि समाज और सरकार को जगाने के लिए अभी और तपस्वियों की बलि की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि तीन–तीन तपस्वियों की बलि लेने के बाद भी देश की लोकतांत्रिक सरकार आराध्या गंगा मां की सुरक्षा एवं उनके संरक्षण के विषय में कब चेतेगी। गंगा की सुरक्षा एवं संरक्षण के नाम पर धन लूटा रही सरकार यथार्थ के धरातल पर आकर गंगा संरक्षण का वास्तविक कार्य कब करेगी। यदि सरकार एवं समाज द्वारा किया गया कोई प्रयास इस दिशा में संभव हुआ तो इन हुतात्माओं के लिए समाज की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि गंगा है तो देश है, गंगा है तो संस्कृति है, सभ्यता है। गंगा नहीं तो न देश रहेगा और न ही उसकी संस्कृति और न सभ्यता। ❑❑

जीएम फसलों द्वारा पारिस्थितिकी असंतुलनः वैज्ञानिक सत्य

केंद्र सरकार द्वारा बी.टी. बैगन, बी.टी. मक्का और जी.एम. सरसों की प्राकृतिक खेती की अनुमति को स्वदेशी जागरण मंच के विरोध के कारण ही रोका जाना संभव हो सका है। यदि हमें हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, एवं जैव विविधता को संरक्षित रखना है तो भारत में जीएम फसलों को किसी भी प्रकार से कृषि में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

– डॉ. रेखा भट्ट

भारत हजारों वर्षों से फसलों में अनुवांषिक सुधार द्वारा बेहतर कृषि उत्पादकता का केंद्र रहा है। यहाँ कृषकों द्वारा पारंपरिक विधियों से अधिक उत्पादन करने व कृषि की सरल क्रियाविधि अपनाने में फसलों के अनुवांषिक सुधार हेतु प्रयोग किये जाते रहे हैं। प्राकृतिक विधि से प्रकीर्णण, संकरण आदि प्रक्रियाओं पर आधारित हजारों वर्षों के अनुप्रयोगों के बाद फसलों के जंगली पूर्वजों की तुलना में अधिक उपज के गुण और नई विषेषताओं को वर्तमान फसलों में सम्मिलित किया जा सका है। जंगली पौधों के प्रकृति में अधिक समय तक संरक्षित रह सकने के गुण को भी कृषि योग्य फसलों में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार पारंपरिक एवं प्राकृतिक विधियों से कृषि में उत्पादन बढ़ता रहा और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्य आपूर्ति संभव हो सकी थी।

वर्ष 2000 के बाद भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में जैव संबर्धित जीएम फसलों का प्रचलन प्रारंभ कर दिया गया। प्राकृतिक रूप से फसलों के अनुवांषिक सुधार में लगने वाले अनेक वर्षों के अन्तराल एवं अनुप्रयोगों की अनिष्चिता को सीमित एवं उपयोगी बनाने के लिये वर्तमान वैज्ञानिकों द्वारा अनुवांषिक संषोधन प्रौद्योगिकी (Genetic modified engineering) का आविष्कार किया गया। संक्षिप्त में जिसे जीएम प्रौद्योगिकी कहते हैं। अनुवांषिक संषोधन के लिये किसी विषेष गुण वाले जीन को भिन्न प्रजाति के स्रोत से पृथक कर फसलीय पौधे की कोषिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रौद्योगिकी द्वारा केवल एक नई विषेषता वाले जीन को चयनित फसल के जीनोम (Genome) में जोड़कर एक नई फसल प्राप्त की जा सकती है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी जिस तरह के जीन स्थानांतरण की अनुमति देती है वह पारंपरिक व अन्य स्थानान्तरण विधियों से प्राप्त करना असंभव होती है।

जीएम प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त फसल के बेहतर होने के तीन मुख्य कारण माने जाते हैं, **पहला**– जो गुण चयनित फसल में उपस्थित नहीं होता उसे पूरी तरह अलग जाति के जीव

या जीवाणु द्वारा सफलतापूर्वक उस प्रजाति में पारित किया जा सकता है। **दूसरा**– लिये गये जीन के साथ में उपस्थित अतिरिक्त जीनों के स्थानान्तरित होने की समस्या से बचा जा सकता है और केवल विषिष्ट गुण वाले जीन को जोड़ना संभव होता है, **तीसरा**– चयनित जीन संयोजनों के गुण, कई पीढ़ियों के अंतराल के बाद प्रकट होने के स्थान पर एक उत्पादन में ही दिखाई देने लगते हैं।

जीएम फसलों के अंतर्गत प्रयोगषाला में अनुवांषिक रूप से उन्नत बनाये गये पौधे खेती के लिये कृषि क्षेत्रों में स्थानान्तरित किये जाते हैं। जहाँ देषज एवं जंगली प्रजातियों के साथ जीएम फसलें स्वयं को स्थायी प्रजाति के रूप में स्थापित कर लेती है। इस तरह सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में जीएम फसलों के सम्मिलित होने से सभी जैविक समुदायों पर अत्यंत सूक्ष्म, स्थायी तथा दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं।

जीएम फसल में डीएनए संषोधन द्वारा किसी चयनित जीन की विषेषताओं को सीमित नहीं किया जा सकता। स्थानांतरित जीन किसी भी पौधे के एक लक्षण को नियंत्रित नहीं करता वरन् कई प्रकार के अनपेक्षित लक्षणों को नियंत्रित करता है। इन लक्षणों से उत्पन्न दुष्प्रभावों को जीन स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान तुरन्त नहीं पहचाना जा सकता। इस तरह विभिन्न कोषिकाओं में किसी नए जीन का समावेष उस पौधे की सम्पूर्ण जीन अभिव्यक्ति को बदल सकता है।

सामान्य रूप से दाता जीव में स्थित जीन एक निष्चित स्थान पर निर्धारित विषिष्टता के साथ अपने गुणों की अभिव्यक्ति करता है, किन्तु जीएम प्रौद्योगिकी में जीन को नई कोषिका में स्थानांतरित तो किया जा सकता है, उसकी पूर्व नियत स्थिति निर्धारित नहीं हो पाती है। अतः कोई भी नया जीन यादृच्छिक (randomly) रूप से कोषिका में किसी भी स्थिति पर जा सकता है, उस स्थिति की सामान्यतया पहचान नहीं हो पाती। इसके तात्कालिक परिणाम जीएम कॉटन में कपास के गोलों का विरूपण तथा जीएम सोया में बढ़ी हुई लिग्निन की मात्रा के रूप में देखे गये हैं। जीन स्थानान्तरण की प्रक्रिया के दौरान जीनों का पुनर्विन्यास हो जाने या जीनों के एकीकृत हो जाने के कारण उत्पन्न विकृति से युक्त नई जीएम फसल प्राकृतिक प्रजातियों के साथ सम्मिलित हो सकती है।

रूपांतरण, संयुग्मन एवं पारगमन जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विदेषी अथवा बाहरी जीन अन्य पौधों या जीवाणुओं द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। बाहरी जीनों के प्राकृतिक रूप से स्थानान्तरण की प्रक्रिया पार्ष्व या क्षैतिज जीन स्थानान्तरण, (Horizontal gene transfer) HGT कहलाती है। प्रकृति में प्रवेष करायी गई फसलें कम समय में उपज देने के विषिष्ट गुण के कारण तेजी से विकसित होती है। और देषज फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर प्राकृतिक चयन का दबाव बढ़ाती है। इस प्रतिस्पर्धा से अनाज की प्राकृतिक किस्में एवं वनस्पतियाँ धीरे–धीरे नष्ट होने लगेगी और जैव विविधता का क्षरण होगा। इस तरह HGT के कारण जंगली प्रजातियों की अनुवांषिक रूप से उपयोगी विषिष्टताएँ समाप्त हो जायेगी और उनके परिस्थितिकी व्यवहार में अन्तर आयेगा जो संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न करेगा। HT मक्का को वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा जैव विविधता क्षरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली फसल मान लिया गया है।

पार्श्व जीन स्थानान्तरण द्वारा पौधों में नये प्रकार का प्रवेशित जीन यदि रोगजनक सूक्ष्म जीवाणुओं में स्थानांतरित हो जाता है तो पौधों में नये प्रकार के रोगों का उद्भव होगा।

जीन रूपांतरण के कारण अफ्रीका में घास की कई प्रजातियाँ संक्रमित पाई गई। ट्रांसजेनिक डीएनए के प्राकृतिक रूप से फैलने के कारण एकबीजपत्री पौधों के नाभिक से यूडिकोट (eudicot) परजीवी जीन, विचवीड (witchweed) नामक घास के जीनोम में प्रवेष कर गये है और घास के अतिरिक्त कई अन्य जंगली प्रजातियों से देषज प्रजातियाँ भी संक्रमित हो गयी है। वहाँ अनेक नई जीएम प्रजातियाँ विकसित हो रही है जिनमें कीटों और खरपतवार नाषकों के लिये प्रतिरोधक क्षमता मूल जीएम फसल की तरह विकसित होती जा रही है।

पार्ष्व जीन स्थानान्तरण द्वारा पौधों में नये प्रकार का प्रवेषित जीन यदि रोगजनक सूक्ष्म जीवाणुओं में स्थानांतरित हो जाता है तो पौधों में नये प्रकार के रोगों का उद्भव होगा। इस तरह के ट्रांसजनिक जीन के प्राकृतिक स्थानांतरण द्वारा जैविक तथा अजैविक घटनाक्रम में असंतुलन उत्पन्न होंगे जो परिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकाल में अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचायेंगे। कुछ जीवों की जनसंख्या में अचानक आई गिरावट इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे जैविक कीट नियन्त्रक के रूप में सन् 1930 से बीटी (BT-Bacillus Thuringiensis) जीन का उपयोग किया जा रहा है। इस जीन द्वारा फसल में ट्रांसजैनिक लक्षण उत्पन्न किया जाता है और वे पौधे विषाक्त कीटनाषी पदार्थ Cry1AC उत्पन्न करने लगते हैं। इन फसलों से प्राप्त बीटी परागकणों की, प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जहरीली

खुराक के लम्बे समय से सेवन के कारण मोनार्क (Monarch) तितलियों के लार्वा की जनसंख्या में तेजी से कमी आयी है। चीन में बीटी कॉटन की फसल में बीटी जीन केवल बॉलवॉर्म नामक कीटों को नियंत्रित करते रहे और बीटी कॉटन में दूसरे प्रकार के (Mirid bug) मिरिड बग नामक कीट प्रभावी हो गये। वहीं भारत के महाराष्ट्र में बालवॉर्म कीट धीरे–धीरे बीटी प्रतिरोधी हो गये, इस कारण कई गुना अधिक कीटनाषकों की आवष्यकता पड़ने लगी। किसानों द्वारा इस आर्थिक भार को ऋण लेकर वहन किया गया तो भी जीएम कपास की फसल को अन्य कीटों से तथा बीटी जीन के प्रभावी होने की अवधि से पहले या बाद की अवस्था में कीटों के प्रकोप से नहीं बचाया जा सका।

इसी तरह राउण्ड–अप नाम से प्रचलित खरपतवारनाषको, गलाइफोसेट व ग्लूफोसिनेट लम्बे समय से बीटी फसलों पर प्रयोग किये जा रहे हैं। इससे प्रतिरोधी खरपतवार वनस्पतिऔ में अधिक संख्या में फैलने लगी। इन वनस्पतियों पर आश्रित शाकाहारी जीवों, पराग पर आश्रित एवं परागण के लिये उत्तरदायी कीटों की संख्या पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और आज अनेक कीट प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। इस तरह कीटों व कई जीवों की प्रजातियाँ नष्ट होने से खाद्य श्रृंखला टूटती जा रही है और परिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है।

जीएम फसलों के उत्पादन से प्राप्त बीजों की उत्पादन क्षमता नष्ट हो जाती है। अतः प्रत्येक बुवाई में कृषक को नए बीज खरीदने के लिए इन बीजों से एक ही प्रकार की फसल की प्रजाति के लगातार उत्पादन से, एकल फसल (mono culture) संस्कृति का चलन, जैव विविधता के लिये खतरा बन गया है।

जीएम फसलों को कृषि अनुसंधान प्रयोगषाला से एक बार खेतों के प्राकृतिक वातावरण में लाये जाने के बाद उत्पन्न जैविक एवं पारिस्थितिकी असंतुलन जैसी समस्याओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। अतः यह आवष्यक है कि सुरक्षित व लाभदायक जीएम फसलों की वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि की जाये। पूरे विष्व में कीटनाषक, किसानों को महंगे खरपतवारनाषक व बीजों को बेचकर भारी मुनाफा कमाने वाली एकमात्र मोन्सेंटो कंपनी कृषि शोध संस्थानों एवं विष्वविद्यालयों को बड़ी राषि वित्तीय सहायता के रूप में देती है तथा वैज्ञानिक तथ्यों को प्रकट नहीं करने देती। अमेरिका में 90 प्रतिषत जीएम खाद्य पदार्थ उपयोग में लिये जाते हैं किन्तु उन पर जीएम अंकित नहीं करके सूचना के अधिकार पर भी मोन्सेन्टो जैसी कंपनी का नियंत्रण है।

यदि हमें हमारे पारिस्थतिकी तंत्र, एवं जैव विविधता को संरक्षित रखना है तो भारत में जीएम फसलों को किसी भी प्रकार से कृषि में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

महाराष्ट्र व दक्षिण के अन्य प्रांतों में लाखों किसानों द्वारा बीटी कपास की खेती में नुकसान के नतीजों एवं हजारों किसानों की आत्महत्या के बाद भी पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा बी.टी. बैगन, बी.टी. मक्का और जी.एम. सरसों की प्राकृतिक खेती की अनुमति को स्वदेषी जागरण मंच के विरोध के कारण ही रोका जाना संभव हो सका है। यदि हमें हमारे पारिस्थतिकी तंत्र, एवं जैव विविधता को संरक्षित रखना है तो भारत में जीएम फसलों को किसी भी प्रकार से कृषि में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

मोन्सेन्टो खेती में विकास एवं नवाचार लाने के नाम पर पूर्णतः अप्राकृतिक जीन स्थानांतरण को वैध बनाकर किसानों को आर्थिक लाभ देने तथा पूरे विष्व में खाद्य आपूर्ति की समस्या से निपटने का दावा करती है। इन दावों के आधार पर जीएम फसलों से उत्पन्न होने वाले मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय खतरों को ये कंपनी निर्विवाद बना देती है।

पर्यावरण विदों के अनुसार ट्रांसजेनिक फसलों द्वारा नये जीन के खाद्य श्रृंखला में आये प्रवाह को तब तक पर्यावरण समस्या नहीं बनाया जा सकता जब तक वह प्रत्यक्ष रूप से अवांछित घातक परिणाम न देने लगे। अभी तक ट्रांसजैनिक HT फसलों के पारिस्थितिकी असंतुलन जैसे दीर्घकालिक प्रभाव की मात्रा को मापना संभव नहीं हो सका है अतः वैष्विक स्तर पर जैविक सुरक्षा मापदण्डों के अनुसार निर्धारित मात्रा में पर्यावरण हानि के प्रमाण प्राप्त नहीं होने तक अपने आर्थिक लाभ के लिये मोन्सेन्टो जैसी कम्पनियाँ मानव स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा हानि पर्यावरण को पहुँचा कर सम्पूर्ण मानवता के साथ खिलवाड़ करती रहेगी।

यदि हमें हमारे पारिस्थतिकी तंत्र, जैव विविधता को संरक्षित रखना है तो जीएम फसलों को किसी भी प्रकार से कृषि में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ❑❑

चीन दा माल ना भई ना, स्वदेशी माल हां भई हां

चीन दा ना भई ना, स्वदेशी माल हां भई हां। खालसा कालेज आफ इंजीनियोरग एंड टेक्नोलॉजी में यह नारा लगाते हुए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बाजार में बिकने वाले चाईनीज सामान का वहिष्कार करने के लिए लोगों को उत्साहित किया। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सम्मेलन में मुख्य तौर पर पहुंचे अखिल राष्ट्रीय संकटक कश्मीरी लाल ने कहा कि देश में धड़ा–धड़ आ रहे चाईनीज सामान ने देश के छोटे कारोबारियों को भारी धक्का लगाया है, जिससे उनका खासा नुक्सान हुआ है। उन्होंने कहा कि छोटा कारोबारी तबाह होने से सिर्फ उसका ही नुक्सान नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़े स्तर पर गिरावट आई है, जिसे उठाने के लिए समूह देशवासियों को स्वदेश सामान को पहल के आधार पर इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि बात करें बाजार में मिलने वाले मिटटी के तवे की तो उस पर बनने वाली रोटी का मनुष्य की सेहत पर बड़ा असर करती है, क्योंकि देखने में आया है कि मिट्टी के तवे पर बनी रोटी खाने से व्यक्ति को गैस की बीमारी नहीं होती है।

स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि जब तक हम अपने देश किसान व छोटे कारोबारी को ऊपर उठाने के लिए स्वदेशी माल को पहल नहीं देंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी और न ही हम सेहतमंद रह सकेंगे। इस मौके पर जेपी सिंह, जगमोहन सिंह, संजीव महाजन, राज कुमार, दीपक कुमार, अविनाश शैला, दीपक बब्बर, गोप चंद, मुनीश शर्मा आदि मौजूद थे।

https://www.jagran.com/punjab/amritsar-china-da-mala-na-na-bhai-na-swadeshi-bharat-hai-bhai-yes-18582449.html

स्वदेशी से ही दूर होगी बेरोजगारी

स्वदेशी जागरण मंच की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने 'एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र' की वकालत करते हुए देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मंच के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दत्तोपंत ठेंगड़ी को श्रद्धांजलि भी दी।

मुख्य अतिथि व मंच के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्विनी महाजन ने कहा कि पूरा विश्व जीडीपी बढ़ाने को पूंजीवादी एवं समाजवादी नीतियां अपना रहा है जिसका असर प्राकृतिक संसाधनों में कमी के साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योगों पर दिखायी दे रहा है। कारीगरों से हाथ से रोजगार छीने जा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं परिवारवाद की परिकल्पना समाप्त हो रही है। इससे बचने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के सिद्धांतों पर चलकर ही स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने स्वामी सानंद के बताए अनुसार नदियों की अविरलता व जल संरक्षण पर भी जोर दिया। प्रांत सह प्रचारक देवेंद्र ने स्वामी सानंद के विचारों को सामाजिक समरसता, सामाजिक उत्कृष्टता एवं राष्ट्र के विकास का आधार बताया।

https://www.amarujala.com/dehradun/11541967107-dehradun-news

उर्जित पटेल सरकार के साथ मिलकर काम करें, वरना इस्तीफा दें: स्वदेशी जागरण मंच

मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच तनातनी चल रही है। पिछले कुछ दिनों से यह खुलकर जाहिर भी हुई है। इन खबरों के बीच स्वदेशी जागरण मंच ने गवर्नर उर्जित पटेल को लेकर बड़ा बयान दिया है।

स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिये अन्यथा वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच का यह बयान ऐसे समय आया है जब सरकार और आरबीआई के बीच विभिन्न मुद्दों पर तनाव बढ़ रहा है। मंच के सह–संयोजक अश्निनी महाजन ने पीटीआई से कहा, "आरबीआई के गवर्नर को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिये वरना वह इस्तीफा दे सकते हैं।"

महाजन ने कहा कि केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर के साथ–साथ अन्य अधिकारियों को सरकार के साथ किसी भी तरह की असहमति होने पर सार्वजनिक तौर पर बोलने से बचना चाहिये। महाजन ने कहा यदि सरकार के साथ किसी मुद्दे पर असहमति है तो उसे सार्वजनिक तौर पर नहीं बल्कि बैंक के निदेशक मंडल में उठाना चाहिये।

सरकार और आरबीआई के बीच मतभेद तब उजागर हुए, जब बीते मुंबई के एक कार्यक्रम में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉ. विरल आचार्य ने कहा था कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को कमजोर करना 'विनाशकारी' हो सकता है। जिस पर बाद में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई पर भड़ास निकालते हुए कहा था कि जब एनपीए बंट रहा था,

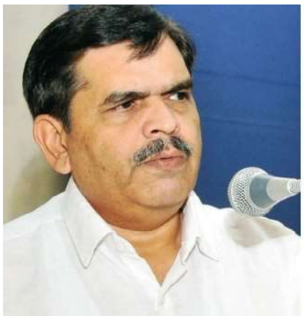

तब आरबीआई भी चुप रहा। हालांकि बाद में वित्तमंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि आरबीआई की स्वायतत्ता जरूरी है और इसका सरकार सम्मान करती है। सरकार और आरबीआई को मिलकर जनहित में काम करना चाहिए।

माना जाता है कि आरबीआई और सरकार के बीच मतभेदों की शुरुआत दरअसल उस समय हुई जब सरकार ने दो माह पहले आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच से ताल्लुक रखने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कहे जाने वाले एस गुरुमूर्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अंशकालिक निदेशक बनाया। यह भी माना जाता है कि नवंबर 2016 में हुए नोटबंदी के फैसले में भी दिमाग एस गुरुमूर्ति का ही था। गौरतलब है कि उर्जित पटेल को आरबीआई का गवर्नर बनाए जाने के तीन माह के भीतर ही सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक में नियुक्त होने से पहले तक गुरुमूर्ति आरबीआई की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। इसी साल जुलाई में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि, "भारत के केंद्रित समाधान तलाशने के बजाय आरबीआई वैश्विक विचारों के अधीन काम कर रहा है। ऐसा करके रघुराम राजन ने आरबीआई की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाया है। आरबीआई अब इस लाइन से हट नहीं सकेगा, क्योंकि उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा से अलग होने का डर रहेगा। आरबीआई ने भारत के लिए सोचने की अपनी क्षमता खो दी है।"

बता दें कि एस. गुरुमूर्ति ने डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य की पिछले सप्ताह की टिप्पणियों को लेकर केंद्रीय बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल से शिकायत भी की है।

https://www.outlookhindi.com/country/india/rss-affiliated-swadeshi-jagran-manch-said-rbi-guv-should-work-in-sync-with-govt-or-resign-32167

राज्यों को जीएसटी मुआवजा भुगतान घटकर 11,900 करोड़

राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे का भुगतान घटकर अगस्त–सितंबर में 11,900 करोड़ रुपये से कुछ अधिक रह गया है। जून–जुलाई के लिए यह मुआवजा 14,930 करोड़ रुपये था, जो अप्रैल–मई महीने के 3,899 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब चार गुना रहा। राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान हर दो महीने पर किया जाता है। एक अधिकारी कहा कि एकीकृत जीएसटी (आइजीएसटी) फंड के रेगुलर और एडहॉक निपटारे के बाद अगस्त–सितंबर के लिए जीएसटी मुआवजा फंड से राज्यों को 11,900 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं। जीएसटी से अक्टूबर में सरकार को रिकॉर्ड 1,00,710 करोड़ रुपये की उगाही हुई। अक्टूबर में दाखिल किए गए रिटर्न और कर की वसूली सितंबर में हुई खरीद और बिक्री को प्रदर्शित करती है।

सरकार ने नियमित निपटान के तहत आइजीएसटी से स्टेट जीएसटी में 15,107 करोड़ रुपये का निपटान किया है। इसके साथ ही अक्टूबर के अंत में प्रोविजनल आधार पर केंद्र के पास बचे हुए आइजीएसटी फंड में से भी राज्यों को 15,000 करोड़ रुपये का निपटान किया गया है। नियमित और प्रोविजनल सेटलमेंट के बाद अक्टूबर में राज्यों की कुल राजस्व आय 52,934 करोड़ रुपये थी। अप्रैल से अगस्त के बीच सर्वाधिक राजस्व घाटा दर्ज करने वाले 10 राज्यों में रहे पुदुच्चेरी (42 फीसदी), पंजाब और हिमाचल प्रदेश (36 फीसदी प्रत्येक), उत्तराखंड (35 फीसदी), जम्मू एवं कश्मीर (28 फीसदी), छत्तीसगढ़ (26 फीसदी), गोवा (25 फीसदी), ओडिशा (24 फीसदी), कनार्टक और बिहार (20 फीसदी) हैं। जीएसटी लागू होने के बाद पिछले वित्त वर्ष की बची अवधि (जुलाई 2017 से मार्च 2018) में राज्यों के जीएसटी राजस्व का घाटा औसतन 16 फीसद रहा। यह चालू वित्त वर्ष की अप्रैल–अगस्त अवधि में घटकर 13 फीसद पर आ गया है।

https://www.jagran.com/business/biz-gst-compensation-to-states-reduced-to-11900-crores-18628419.html

बिहार में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल, बजट 5540 करोड़ रु.

बिहार में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (पीएमसीएच) विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। इस अस्पताल को लेकर नीतीश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य कैबिनेट ने विश्व का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले कुछ सालों में बिहार के लोगों को इलाज के लिए मुंबई या अन्य शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

विश्व के सबसे बड़े इस अस्पताल के लिए 5540करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पीएमसीएच अस्पताल का विस्तारीकरण तीन चरण में सात वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस काम को और भी पहले कर लेने की आवश्यकता जताई है।

अस्पताल परिसर में 450 बेड का धर्मशाला बनाया जाएगा। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि फिलहाल बेलग्रेड (सार्बिया) में 3500 बेड का अस्पताल है। आने वाले दिनों में पीएमसीएच विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा। फिलहाल यहां बेड की संख्या 1700 है। यहां एमबीबीएस की सीटों की संख्या को 150 से बढ़ा कर 250 किया जाएगा। वहीं, पीजी सीटों की संख्या को 146 से बढ़ा कर 200 करने का प्रस्ताव है। सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या 8 से बढ़ा कर 36 की जाएगी। यह अस्पताल पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग होगा। अशोक राजपथ से कनेक्टिविटी के अलावा इसे कारगिल चौक से अशोक राजपथ पर बनने वाले डबल डेकर पुल और गंगा एक्सप्रेस–वे से भी जोड़ा जाएगा।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-POLI-ECNM-worlds-largest-hospital-in-bihar-budget-rs-5540-crore-5978595-PHO.html?sld_seq=1

भारत के साथ फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाना चाहते हैं यूरोपीय देश

भारत द्वारा ब्रिटेन और जर्मनी के लिए स्थापित फास्ट ट्रैक सिस्टम की सफलता को देखते हुए कई और यूरोपीय देशों ने इस नई व्यवस्था में रुचि दिखाई है। यह व्यवस्था भारत में कारोबार वाली कंपनियों और निवेशकों की समस्याओं की पहचान और निराकरण में मदद करती है।

भारत ने ब्रिटेन और जर्मनी के साथ इस तरह की व्यवस्था स्थापित की हुई है। इन दोनों देशों के लिए भारत का फास्ट ट्रैक सिस्टम अलग–अलग है। इटली और हॉलैंड के साथ भी इस सिस्टम को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। ये यूरोपीय देश भी अपने यहां इसी तरह की प्रणाली स्थापित करेंगे, ताकि इन देशों में निवेश वाली भारतीय कंपनियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

https://www.jagran.com/business/biz-european-nations-want-fast-track-system-with-india-to-facilitate-18619215.html

अमेरिका को पीछे छोड़ स्मार्टफोन का दूसरा बड़ा बाजार बना भारत

इस साल जुलाई से सितंबर की तिमाही में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया। शोध कंपनी कैनालिस के एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल की तीसरी तिमाही में भारत में 4.04 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई। वहीं 10.06 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री के साथ चीन पहले स्थान पर रहा। अमेरिका में इस अवधि में चार करोड़ स्मार्टफोन बिके।

कैनालिस ने कहा कि जुलाई–सितंबर, 2018 के दौरान दुनियाभर में सालाना आधार पर स्मार्टफोन की बिक्री में 7.2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इस अवधि में दुनिया भर में 34.89 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई। यह लगातार चौथा साल है, जब स्मार्टफोन की बिक्री में कमी आई है।

https://www.livehindustan.com/business/story-after-left-behind-america-now-india-become-world-second-largest-market-of-smartphones-2258667.html

अमेरिका ने कुछ प्रतिबंधों से भारत को छूट दी

अमेरिका ने ईरान में विकसित किए जा रहे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह और इसे अफगानिस्तान से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारत को कुछ प्रतिबंधों से छूट दे दी है। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला दिखाता है कि ओमान की खाड़ी में विकसित किए जा रहे इस बंदरगाह में भारत की भूमिका को अमेरिका मान्यता देता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि एक दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए और छूट देने में उसका रुख बेहद सख्त है। यह बंदरगाह युद्ध ग्रस्त अफगानिस्तान के विकास के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विदेश मंत्रलय के एक प्रवक्ता ने प्रेट्र को बताया कि गहन विचार के बाद विदेश मंत्री ने 2012 के ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार रोधी अधिनियम के तहत लगाए गए कुछ प्रतिबंधों से छूट देने का प्रावधान किया है जो चाबहार बंदरगाह के विकास, उससे जुड़े एक रेलवे लाइन के निर्माण और बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के इस्तेमाल वाली, प्रतिबंध से अलग रखी गई वस्तुओं के नौवहन से संबंधित है। साथ ही यह ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों के देश में निरंतर आयात से भी जुड़ा हुआ है।

https://www.jagran.com/business/biz-us-exempts-india-from-certain-sanctions-for-development-of-chabahar-port-in-iran-18616717.html

स्वदेशी के समर्थक थे अनंत कुमार

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का न होना स्वदेशी जागरण मंच के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे मंच के पारिवारिक सदस्य की तरह थे। प्रायः प्रत्येक मौके पर उन्होंने मंच की गतिविधियों में खुले मन से भागीदारी की तथा जरूरत पड़ने पर बढ़–चढ़कर स्वदेशी आंदोलनों को दिशा देने का भी काम किया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। कैंसर से जिंदगी की लड़ाई वह नहीं जीत पाए। कैंसर की दवा सस्ती हो इसके लिए रसायन और उर्वरक मंत्री रहते हुए अनंत कुमार ने पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की और इसमें उन्हे कामयाबी भी मिली। उनके प्रयास से ही कैंसर और कई अन्य गंभीर बीमारियों की दवा 86 फीसदी तक सस्ती हुई।

कैंसर की दवा सस्ती हो इसके लिए अनंत कुमार यदि पूरे मनोभाव से जुड़े रहे तो उसके पीछे उनकी एक निजी कहानी भी है। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे। बंगलुरू में रेलवे कॉलोनी में ही रहते थे। उनकी माता को कैंसर हो गया था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। डाक्टरों ने उनकी माता का इलाज किया। कैंसर की दवा दी और कहा कि दिन में दो टैबलेट खाना है। लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से रोजाना दो टैबलेट वह अपनी मां को नहीं दे सकते थे। इसलिए दो कि जगह रोजाना एक ही टैबलेट वह अपनी मां को दे पाते थे। महंगी दवा की वजह से उनकी मां को उचित इलाज नहीं हो सका और वह कैंसर की वजह से ही चल बसी थी।

बाद में जब वह सांसद बने और फिर मंत्री तो उन्होंने कैंसर मरीजों की भरसक मदद की और करवाई भी। मोदी सरकार में जब वह रसायन और उर्वरक मंत्री बने तो उन्होंने कैंसर की दवा की कीमत कम करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन इसे विधि का विधान कहें या विड़ंबना कैंसर के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले अनंत कुमार अपनी मां की तरह ही कैंसर के कारण ही कम उम्र में ही काल के गाल में समा गये। स्वदेशी जागरण मंच नम आंखों से उनके योगदान का हमेशा आभारी रहेगा। ❑

बेमानी है आरबीआई की स्वायत्तता की बातें

भारतीय रिजर्व बैंक भी संविधान के दायरे में बंधा है। देशहित में निर्णय लेने वाली सरकार के साथ उसे कदम मिलाकर चलना होगा। केंद्र सरकार के साथ बढ़ती हालिया तल्खियों के बीच बैंक का यह कहना कि उसकी स्वायत्तता पर हमला है, गलत है। रिजर्व बैंक बनाम भारत सरकार विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि राजन ने ब्याज दरें कम की होती तो आज हालात कुछ और होते। महाजन ने राजन पर डालर के मुकाबले रूपये की कीमत को गिरने देने का भी आरोप लगाया। साथ ही मुद्रा योजना को ठीक ढंग से लागू न करवा पाने का भी दोषी ठहराया। राजन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि राजन ने जहां से शिक्षा–दीक्षा प्राप्त ही है, उनके विचारों और नीतियों में भी वहीं झलकता है।

महाजन ने कहा कि देशहित में नीतियां बनाने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, न कि आरबीआई। आरबीआई को हर हाल में सरकार की बात माननी चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों पर जाकर बात करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसे हालात आये हैं जब सरकारों को आरबीआई को चेताने की जरूरत पड़ी है।

विदेश में चीनी बेचने की संभावना देख रही सरकार

केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों का बकाया चुकाने को कमर कस ली है। उसने चीनी मिलों को बकाया चुकाने के लायक बनाने को निर्यात को बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। चीनी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तीन टीम पांच देशों के दौरे पर हैं। वह चीन, बांग्लादेश, मलयेशिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में निर्यात की संभावनाएं तलाश रही हैं। निर्यात बढ़ने से मिलों को अच्छे दाम मिलेंगे और वह बकाया चुकाने में सक्षम होंगी। सरकार ने चीनी मिलों के लिए न्यूनतम सांकेतिक कोटा (एमआईईक्यू) के तहत 20 लाख टन चीनी निर्यात करना हाल ही में तय किया था। मिलों ने फिलहाल 8 लाख टन चीनी निर्यात का सौदा किया है और सरकार चाहती है कि देश में होने वाले करीब 65 लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों में भेजा जाए। ❑❑

https://www.amarujala.com/business/central-government-looking-at-the-possibility-of-selling-sugar-in-abroad

स्वदेशी मेला, द्वारका, दिल्ली

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) सेक्टर–7, द्वारका, नई दिल्ली में 24 से 29 अक्टूबर, 2018 को स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। स्वदेशी मेले में 150 से अधिक स्टॉल की भागीदारी रही। मेले में सरकारी योजनाओं के साथ–साथ आयुष विभाग द्वारा यूनानी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा आदि की जानकारी रही। स्वदेशी मेले में कुछ नए आयाम/प्रयोग भी शुरू किए गए, जिसके अंतर्गत 26–27 अक्टूबर को 'स्वदेशी संवाद' नाम से एक विशिष्ट पहल शुरू की गई, जिसमें जन–प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएँ एवं स्वदेशी के बीच संवाद हो। ऐसी योजना के तहत 26 अक्टूबर को पश्चिमी–दिल्ली के सामाजिक संस्था, प्रशासनिक अधिकारी एवं क्षेत्रीय सांसद प्रवेश वर्मा उपस्थित रहे। इसमें लगभग 65 संस्थाओं की भागीदारी रही। 27 अक्टूबर को दक्षिणी–दिल्ली की सामाजिक संस्थाएँ एवं क्षेत्रीय सांसद रमेश विधूड़ी उपस्थित रहे, जिसमें लगभग 43 सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी रही।

एक नए प्रयोग के तहत स्वदेशी मेले के पहले तीन दिन (24, 25, 26 अक्टूबर) के लिए स्वदेशी स्टार्टअप फेस्ट हुआ, जिसमें 21 स्टार्टअप्स की स्टॉल रही और तीनों दिन अलग–अलग विषयों पर तीन सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला रही। इस फेस्ट में NSIC, Delhi IIT, ANDC, Shaheed Sukhdev College, VC, Palampur Agri University, Kalini College प्रमुख संस्थाओं की भागीदारी रही। स्वदेशी स्टार्टअप आयाम में श्री कमलजीत (संगठक दिल्ली–हरियाणा) ने बुनियादी भूमिका निभाई। मेले में विभिन्न प्रकार के खेल/प्रतियोगिताएँ रही। जिसमें प्रमुख रूप से बच्चों की चित्रकला, रंगकला, रंगोली, लेमन दौड़, कबड्डी, खो–खो, रस्सा–कस्सी एवं महिलाओं की मेंहदी प्रतियोगिता रही।

मेले में फुटपाथ पर काम करने वालों से लेकर स्वदेशी कॉर्पोरेट जगत सभी के लिए अवसर थे, अर्थात मेले में लुहार, कुम्हार, बुनकर, स्वदेशी कॉर्पोरेट, मदर डेयरी, क्विक हील एंटी वॉयरस से लेकर सोलर आदि सभी के स्टॉल शामिल थे। शिल्पकारों ने पारंपरिक उपकरण जैसे हथकरघा, बुनाई में उपयोग लाई जाने वाली खड्डी, कुम्हार द्वारा चाक का भी प्रदर्शन रहा। स्टॉल में प. बंगाल, जम्मू कश्मीर, उ.प्र., बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान समेत 12 राज्यों से अधिक उद्यमियों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपने उत्पादों की बिक्री की।

मेले में एक स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं, जिसमें पुराने समय में घर एवं खेती में उपयोग होने वाले सभी औजार, वस्तुओं की प्रदर्शनी रही। जिसमें हाथ से मक्खन निकालने वाली रई, खेत–हल, ट्रैक्टर, हस्त–नल, चारा काटने वाला गंटासा, पीतल के बरतनों के साथ–साथ गिर नस्ल की गाय व बेल का जोड़ा भी था। गोबर के उपलें, 'हारा' में गर्म किया गया गाय का दूध, गुड़ व खांड का आनंद मेले में आए लोगों ने लिया। पोरटेबल सिनेमा हॉल नए पी.वी.आर. तर्ज पर पूरा वातानुकूलित मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

मेला संचालन सदस्य रविंद्र सोलंकी, रामनिवास दहिया, नवीन गर्ग, सुरेंद्र मानव, निखिल रंजन, रविन्द्र अग्रवाल, योगेश सैनी, अनिता पांडेय, विकास कौशिक, डॉ. खगेश कुमार, सन्नी गौरव, राहुल भारत, मिथलेश सिंह, सतीश शर्मा, मधु राज, राजेंद्र नेगी, रतन बिष्ट, रेनू शर्मा, संजय उपाध्याय, निलेंद्र पाठक, कैप्टन प्रमोद कुमार, उर्मिल शर्मा, सुनील गर्ग, भीम सिंह, हरिदेव, हेमेंद्र गुप्ता, कविता, नागेंद्र सिंह, प्रवीन सहरावत, सोनू कुमार, अजय राणा, रश्मी पटवाल, प्रमोद कुमार, विक्रम रावत, दिनेश सिंह, राहुल मिश्रा, बृजेश नोटियाल, मोनिका सिंह, बी.पी. चंदेल सहित मेले में आए सभी महानुभाव द्वारा 'स्वदेशी स्वीकार और विदेशी बहिष्कार' की प्रतिज्ञा ली तथा इस प्रकार राष्ट्रीय स्वाभिमान, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशी के संदेश का संप्रेषण सुनिश्चित किया गया।❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

स्टार्ट–अप कार्यक्रम

(नई दिल्ली)

सचित्र झलकियां

हिमाचल प्रांत सम्मेलन

जम्मू-कश्मीर प्रांत सम्मेलन

पंजाब प्रांत सम्मेलन

पंजाब प्रांत सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधिगण

स्वदेशी पत्रिका
डाक तिथि 15–16 नवंबर 2018 नई दिल्ली पी.एस.ओ.
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2018-19-20
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी मेला

(24–29 अक्टूबर 2018, द्वारका, नई दिल्ली)

सचित्र झलकियां

(25 अक्टूबर–1 नवंबर 2018, जमशेदपुर, झारखंड)

सचित्र झलकियां

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती